गरवी गुजरात

PRGI No. GUJHIN/2011/39228

# गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 16
अंक : 062
दि. 01.07.2026,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा


# विदेशी चंदे से ओसीआई सेवाओं तक डिजिटल बदलाव की नई छलांग, एफसीआरए 2.0 और ई-ओसीआई कार्ड से पारदर्शिता, सुरक्षा व सुविधा को मिलेगा नया आयाम

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने विदेशी अंशदान की निगरानी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मंगलवार को एफसीआरए 2.0 पोर्टल और ई-ओसीआई कार्ड की शुरुआत कर दी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में इन दोनों डिजिटल पहलों का शुभारंभ करते हुए कहा कि इनका उद्देश्य शासन व्यवस्था को अधिक आधुनिक, जवाबदेह और नागरिक हितैषी बनाना है। उन्होंने कहा कि नई डिजिटल प्रणाली से जहां विदेशी अंशदान (एफसीआरए) से जुड़े सभी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी, वहीं दुनिया भर में रहने वाले लाखों भारतीय मूल के लोगों को भी ओसीआई सेवाओं में बड़ी राहत मिलेगी। सरकार का दावा है कि इन दोनों प्लेटफॉर्म के लागू होने से कागजी प्रक्रियाओं में भारी कमी आएगी, आवेदन निस्तारण की गति बढ़ेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पहलुओं की निगरानी पहले से कहीं अधिक प्रभावी हो सकेगी।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार तकनीक आधारित सुशासन की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल सेवाओं का डिजिटलीकरण करना नहीं है, बल्कि ऐसी व्यवस्था विकसित करना है, जिसमें ईमानदार नागरिकों और संस्थाओं के लिए प्रक्रियाएं सरल हों तथा कानून का दुरुपयोग करने वाले तत्वों पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके। उन्होंने कहा कि "न्यूनतम सरकार, अधिकतम सुशासन" की अवधारणा को व्यवहार में उतारने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म सबसे प्रभावी माध्यम बन रहे हैं।

गृह मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम यानी एफसीआरए से जुड़ी पूरी व्यवस्था काफी जटिल मानी जाती थी। आवेदन, पंजीकरण, नवीनीकरण, दस्तावेजों की जांच और वार्षिक विवरणियों की प्रक्रिया मुख्य रूप से कागजी कार्यवाही पर आधारित थी। इससे न केवल आवेदकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, बल्कि मामलों के निस्तारण में भी काफी समय लगता था। नई एफसीआरए 2.0 प्रणाली इन सभी समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

उन्होंने बताया कि अब एफसीआरए से संबंधित लगभग सभी सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। पंजीकरण, नवीनीकरण, वार्षिक विवरणी जमा करना, दस्तावेज अपलोड करना, आवेदन की स्थिति जानना तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाएं डिजिटल माध्यम से पूरी की जा सकेंगी। इससे कागजी दस्तावेजों की आवश्यकता लगभग समाप्त हो जाएगी और विभिन्न स्तरों पर होने वाली देरी भी कम होगी।

एफसीआरए 2.0 पोर्टल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता विदेशी अंशदान की रियल टाइम निगरानी है। सरकार का कहना है कि अब विदेशी स्रोतों से आने वाले धन की निगरानी पहले की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकेगी। इससे न केवल वित्तीय पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में भी समय रहते आवश्यक कार्रवाई संभव होगी। गृह मंत्रालय का मानना है कि तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली से वैध और पारदर्शी तरीके से कार्य करने वाले संगठनों को सुविधा मिलेगी, जबकि नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान अधिक तेजी से हो सकेगी।

नई प्रणाली को अत्याधुनिक डिजिटल सुविधाओं से लैस किया गया है। इसमें आधार आधारित प्रमाणीकरण, ई-साइन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन (ओसीआर), एनजीओ दर्पण प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण तथा स्वचालित दस्तावेज सत्यापन जैसी सुविधाएं शामिल की गई हैं। इससे आवेदन प्रक्रिया अधिक सटीक, तेज और पारदर्शी बनने की उम्मीद है। आवेदकों को बार-बार दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता भी कम होगी, क्योंकि विभिन्न सरकारी डेटाबेस के साथ सीधा समन्वय स्थापित किया गया है।

सरकार के अनुसार वर्तमान में देश में लगभग 14,500 सक्रिय एफसीआरए पंजीकृत संगठन कार्यरत हैं। हर वर्ष लगभग 15 से 20 हजार नए अथवा नवीनीकरण संबंधी आवेदन प्राप्त होते हैं, जबकि करीब 17 हजार वार्षिक विवरणियां भी जमा की जाती हैं। इतने बड़े स्तर पर होने वाले कार्यों के प्रबंधन के लिए आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। एफसीआरए 2.0 पोर्टल इसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। सरकार ने बताया कि नए पोर्टल को सरकारी क्लाउड प्लेटफॉर्म 'मेघराज' पर होस्ट किया गया है, जिससे इसकी सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा इसे स्थायी खाता संख्या (पैन), आधार, ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (ओसीआई), एनजीओ दर्पण, विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या (यूडीआईएन) तथा विभिन्न बैंकों सहित कई सरकारी डेटाबेस से जोड़ा गया है। इस एकीकृत प्रणाली से सूचनाओं का सत्यापन स्वतः होगा और आवेदन निस्तारण की प्रक्रिया पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज हो जाएगी।

गृह मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि आने वाले समय में इस पोर्टल को और अधिक उन्नत बनाया जाएगा। इसके तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित चैटबॉट, मोबाइल एप्लीकेशन तथा बैंकों के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड जैसी नई सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। इन सुविधाओं के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को तत्काल सहायता उपलब्ध होगी तथा संबंधित विभागों के बीच समन्वय भी मजबूत होगा।

कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने ई-ओसीआई कार्ड का भी शुभारंभ किया। सरकार का कहना है कि इस पहल से दुनिया भर में रहने वाले 50 लाख से अधिक ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्डधारकों को महत्वपूर्ण सुविधा मिलेगी। अब ओसीआई से जुड़ी पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से पूरी की जा सकेगी, जिससे दस्तावेजों के रखरखाव और नवीनीकरण की जटिलताएं काफी हद तक समाप्त हो जाएंगी। नई व्यवस्था के तहत 20 वर्ष की आयु के बाद नया पासपोर्ट जारी होने पर ओसीआई बुकलेट को दोबारा जारी कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे समय और संसाधनों दोनों की बचत होगी। साथ ही कार्डधारक अपना डिजिटल ओसीआई कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे। इससे कार्ड खो जाने, क्षतिग्रस्त होने अथवा दोबारा जारी कराने जैसी समस्याओं से भी राहत मिलेगी।

सरकार के अनुसार ई-ओसीआई कार्ड का एक महत्वपूर्ण लाभ यह भी होगा कि हवाई अड्डों और आव्रजन केंद्रों पर वास्तविक समय में डिजिटल सत्यापन संभव हो सकेगा। इससे यात्रा प्रक्रिया अधिक तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक बनेगी। अधिकारियों का मानना है कि डिजिटल सत्यापन प्रणाली से फर्जी दस्तावेजों की संभावना भी कम होगी और आव्रजन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि एफसीआरए 2.0 और ई-ओसीआई कार्ड केवल दो नई डिजिटल सेवाएं नहीं हैं, बल्कि प्रशासनिक सुधारों की व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा हैं। एक ओर जहां विदेशी अंशदान की निगरानी को आधुनिक तकनीक से जोड़ा गया है, वहीं दूसरी ओर प्रवासी भारतीय समुदाय को डिजिटल सेवाओं के माध्यम से अधिक सुविधाजनक व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। इससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ने, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आने और नागरिकों का समय बचने की उम्मीद है। सरकार का विश्वास है कि नई तकनीक आधारित इन पहलों से शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और सुरक्षित बनेगी। साथ ही डिजिटल इंडिया अभियान को भी नई मजबूती मिलेगी, जिसमें तकनीक के माध्यम से नागरिक सेवाओं को सरल, तेज और भरोसेमंद बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

## तृणमूल नेता जहांगीर खान पर जांच का शिकंजा और कसा, एसआईटी को मिलीं 60 संपत्तियों की फाइलें; आय के स्रोत और लेनदेन की होगी गहन पड़ताल

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता क्षेत्र से जुड़े तृणमूल कांग्रेस नेता जहांगीर खान और उनकी पत्नी के खिलाफ चल रही जांच अब नए मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। विशेष जांच दल (एसआईटी) को जांच के दौरान करीब 60 अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज मिलने का दावा किया गया है। इन दस्तावेजों के सामने आने के बाद जांच एजेंसियों ने संपत्तियों के स्वामित्व, खरीद-फरोख्त, धन के स्रोत और संबंधित वित्तीय लेनदेन की व्यापक जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का मानना है कि इन दस्तावेजों से मामले के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर नई जानकारी मिल सकती है।

सूत्रों के अनुसार एसआईटी को जिन दस्तावेजों की जानकारी मिली है, उनमें जमीन, आवासीय मकान, फ्लैट और अन्य अचल संपत्तियों से संबंधित रिकॉर्ड शामिल हैं। जांच एजेंसियां अब प्रत्येक संपत्ति के स्वामित्व का अलग-अलग सत्यापन कर रही हैं। यह पता लगाया जा रहा है कि संपत्तियां किसके नाम पर दर्ज हैं, उनकी खरीद कब और किन परिस्थितियों में की गई तथा उनके अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया कानूनी प्रावधानों के अनुरूप थी या नहीं।

जांच अधिकारियों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न इन संपत्तियों के लिए इस्तेमाल किए गए धन के स्रोत को लेकर है। एसआईटी यह जानने का प्रयास कर रही है कि संपत्तियों की खरीद के लिए उपयोग की गई राशि वैध आय से अर्जित की गई थी या उसके पीछे किसी अन्य प्रकार का वित्तीय स्रोत मौजूद था। इसी उद्देश्य से संपत्तियों से जुड़े भुगतान, बैंकिंग रिकॉर्ड और वित्तीय दस्तावेजों की भी गहन पड़ताल की जा रही है।

सूत्रों का कहना है कि जांच केवल संपत्तियों की संख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके पूरे लेनदेन की श्रृंखला को खंगाला जा रहा है। अधिकारियों की टीम यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि प्रत्येक संपत्ति का मूल मालिक कौन था, संपत्ति किस मूल्य पर खरीदी गई, खरीद-बिक्री के दौरान कौन-कौन पक्ष शामिल थे और क्या पंजीकरण तथा अन्य कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। यदि किसी लेनदेन में अनियमितता या संदिग्ध परिस्थितियां सामने आती हैं तो संबंधित पक्षों से पूछताछ भी की जा सकती है।

जांच एजेंसियां इस बात की भी पड़ताल कर रही हैं कि कहीं संपत्तियां किसी दबाव, प्रभाव या अन्य अनुचित परिस्थितियों में तो प्राप्त नहीं की गईं। इसके लिए पुराने स्वामित्व रिकॉर्ड, बिक्री अनुबंध, रजिस्ट्री दस्तावेज और स्थानीय राजस्व अभिलेखों का मिलान किया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित सरकारी विभागों से भी अतिरिक्त जानकारी जुटाई जाएगी।

वित्तीय जांच भी इस मामले का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। एसआईटी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि संपत्तियों की खरीद के दौरान धन का प्रवाह किस प्रकार हुआ। इसके लिए संबंधित बैंक खातों, भुगतान के माध्यमों और वित्तीय लेनदेन का विश्लेषण किया जा सकता है। यदि जांच में आवश्यकता महसूस हुई तो संबंधित बैंकिंग संस्थानों से भी विस्तृत जानकारी मांगी जाएगी, ताकि प्रत्येक लेनदेन की पुष्टि की जा सके। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसियां दस्तावेजों का तकनीकी और कानूनी परीक्षण भी करवा रही हैं। इससे यह स्पष्ट करने का प्रयास होगा कि सभी दस्तावेज वास्तविक हैं या नहीं तथा उनमें किसी प्रकार की अनियमितता, विसंगति अथवा फर्जीवाड़े की संभावना तो नहीं है। दस्तावेजों की पुष्टि के बाद ही जांच की अगली दिशा तय की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल जांच पूरी तरह साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर आगे बढ़ाई जा रही है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी उपलब्ध रिकॉर्ड, वित्तीय लेनदेन, स्वामित्व संबंधी दस्तावेज और संबंधित व्यक्तियों के बयानों का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाएगा। यदि जांच के दौरान नए तथ्य सामने आते हैं तो उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि बड़ी संख्या में अचल संपत्तियों से जुड़े मामलों में जांच प्रक्रिया अक्सर लंबी और जटिल होती है, क्योंकि प्रत्येक संपत्ति के स्वामित्व, भुगतान और पंजीकरण का स्वतंत्र सत्यापन करना पड़ता है। ऐसे मामलों में राजस्व अभिलेख, बैंक रिकॉर्ड, कर संबंधी दस्तावेज और रजिस्ट्री रिकॉर्ड सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिलहाल एसआईटी की जांच जारी है और एजेंसियां दस्तावेजों के आधार पर मामले की विभिन्न कड़ियों को जोड़ने में जुटी हैं। आने वाले दिनों में जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट होगा कि संपत्तियों के अधिग्रहण और वित्तीय लेनदेन में किसी प्रकार की अनियमितता हुई है या नहीं। जांच एजेंसियों का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष और तथ्यों पर आधारित जांच की जाएगी तथा आवश्यकतानुसार आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

## गुवाहाटी में सोने की तस्करी पर अब तक की सबसे बड़ी चोट, 54 करोड़ का 38 किलो सोना जब्त; खुफिया सूचना पर दबिश देकर एक तस्कर गिरफ्तार

गुवाहाटी। असम पुलिस ने अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय सोना तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए लगभग 38 किलोग्राम सोना बरामद किया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 54 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक कथित तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार, हाल के वर्षों में गुवाहाटी में सोने की यह सबसे बड़ी बरामदगी मानी जा रही है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की तह तक पहुंचने और तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई पूर्व में प्राप्त एक विश्वसनीय खुफिया सूचना के आधार पर की गई। सूचना मिली थी कि बड़ी मात्रा में सोने की एक खेप गुवाहाटी के रास्ते आगे भेजी जाने वाली है। इसके बाद शहर के लताशील थाना पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में विशेष अभियान की योजना बनाई। संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखी गई और खारघुली क्षेत्र में घेराबंदी कर कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

अभियान के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को रोककर उसकी तलाशी ली। जांच में उसके कब्जे से भारी मात्रा में सोना बरामद हुआ। प्रारंभिक जांच के बाद बरामद सोने का कुल वजन लगभग 38 किलोग्राम पाया गया, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 54 करोड़ रुपये आंकी गई है। बरामदगी के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और जब्त किए गए सोने को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अक्षय बंसुरे के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, उसके पास से सोने के अलावा चार मोबाइल फोन और 3,700 रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं। जांच एजेंसियां अब मोबाइल फोन के डेटा का विश्लेषण कर यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि आरोपी किन लोगों के संपर्क में था और इस तस्करी नेटवर्क में उसकी भूमिका क्या थी। मोबाइल फोन से प्राप्त कॉल रिकॉर्ड, चैट, लोकेशन और अन्य डिजिटल साक्ष्य जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं, हालांकि जांच के हित में उनका खुलासा फिलहाल नहीं किया गया है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बरामद सोना कहां से लाया गया था, उसका अंतिम गंतव्य क्या था और इस पूरे नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं। यह भी जांच की जा रही है कि कहीं यह खेप किसी अंतरराष्ट्रीय तस्करी गिरोह से तो जुड़ी नहीं थी।

गुवाहाटी पूर्वोत्तर भारत का प्रमुख व्यापारिक और परिवहन केंद्र होने के कारण लंबे समय से तस्करी गतिविधियों के लिहाज से संवेदनशील माना जाता रहा है। सीमावर्ती राज्यों और पड़ोसी देशों से जुड़े मार्गों का इस्तेमाल कर सोना, मादक पदार्थ तथा अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी के प्रयास समय-समय पर सामने आते रहे हैं। ऐसे में इतनी बड़ी मात्रा में सोने की बरामदगी को सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस मामले में विभिन्न जांच एजेंसियों के साथ भी समन्वय किया जा रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि बरामद सोने का स्रोत क्या है और क्या इसका संबंध किसी संगठित अपराध या हवाला नेटवर्क से है। आवश्यकता पड़ने पर अन्य राज्यों की एजेंसियों से भी जानकारी साझा की जाएगी।

जांच के दौरान बरामद सोने की शुद्धता, उसका स्रोत और स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों की भी जांच की जाएगी। यदि आरोपी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो संबंधित कानूनों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वित्तीय लेनदेन और संभावित बैंकिंग रिकॉर्ड की भी जांच की जा सकती है, ताकि पूरे नेटवर्क की आर्थिक गतिविधियों का पता लगाया जा सके।

विशेषज्ञों का मानना है कि हाल के वर्षों में सोने की बढ़ती कीमतों के कारण तस्करी के मामलों में भी वृद्धि देखी गई है। तस्कर सीमा शुल्क और करों से बचने के लिए अवैध रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचता है और संगठित अपराध को बढ़ावा मिलता है। ऐसे मामलों में केवल खेप जब्त करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है।

पुलिस ने कहा है कि गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है और उसके आधार पर आगे और गिरफ्तारियां होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जांच पूरी होने के बाद मामले में विस्तृत आरोपपत्र तैयार किया जाएगा। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में सोना किन माध्यमों से गुवाहाटी तक पहुंचा और इसे आगे कहां भेजा जाना था। इस कार्रवाई को असम पुलिस की हालिया सबसे बड़ी सफलताओं में से एक माना जा रहा है।

## जुलाई में मानसून रहेगा कमजोर, सामान्य से कम बारिश का अनुमान; कई राज्यों में गर्मी और उमस बढ़ने के आसार, खेती और जल संसाधनों पर बढ़ी चिंता

कोलकाता। दक्षिण-पश्चिम मानसून के बीच देशभर के लिए जारी ताजा मासिक पूर्वानुमान ने कृषि, जल प्रबंधन और आम जनजीवन से जुड़ी चिंताओं को और बढ़ा दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मंगलवार को जारी अपने जुलाई माह के पूर्वानुमान में कहा है कि इस बार पूरे देश में औसतन सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार जुलाई के दौरान देशभर में दीर्घकालिक औसत (एलपीए) का लगभग 94 प्रतिशत वर्षा होने का अनुमान है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह अनुमान सही साबित होता है तो इसका प्रभाव खेती, जलाशयों के जलस्तर, पेयजल उपलब्धता और खाद्य उत्पादन पर पड़ सकता है। इसके साथ ही कई क्षेत्रों में गर्मी और उमस का असर भी सामान्य से अधिक महसूस किया जा सकता है। आईएमडी के अनुसार जुलाई भारत के मानसून सीजन का सबसे महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। इसी दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में व्यापक वर्षा होती है और खरीफ फसलों की बुवाई तेज गति से आगे बढ़ती है। इस वर्ष जुलाई में दीर्घकालिक औसत वर्षा के मुकाबले केवल 94 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान जताया गया है। भारत में जुलाई माह की दीर्घकालिक औसत वर्षा 280.4 मिलीमीटर मानी जाती है। ऐसे में अनुमानित वर्षा सामान्य श्रेणी से नीचे रहने की संभावना दर्शाती है कि कई क्षेत्रों में अपेक्षित बारिश नहीं हो पाएगी।

मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि दीर्घकालिक औसत (लॉन्ग पीरियड एवरेज-एलपीए) किसी क्षेत्र में 30 से 50 वर्षों की अवधि के दौरान दर्ज औसत वर्षा का वैज्ञानिक मानक होता है। वर्तमान पूर्वानुमान तैयार करने के लिए वर्ष 1971 से 2020 तक के वर्षा

आंकड़ों को आधार बनाया गया है। इसी आधार पर यह आकलन किया जाता है कि किसी महीने या पूरे मानसून सीजन में वर्षा सामान्य, सामान्य से अधिक अथवा सामान्य से कम रहने की संभावना है। आईएमडी के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि जुलाई के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि देश के कुछ क्षेत्रों में अच्छी वर्षा दर्ज हो सकती है। विशेष रूप से उत्तर-पश्चिम भारत, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पूर्व-मध्य भारत तथा पूर्वी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ क्षेत्रों में सामान्य से सामान्य से अधिक वर्षा होने का अनुमान है। इन क्षेत्रों में मानसून की सक्रियता अपेक्षाकृत बेहतर रहने की संभावना जताई गई है।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून पूरे देश में समान रूप से सक्रिय नहीं रहता। कई बार कुछ क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा होती है, जबकि अन्य हिस्सों में बारिश की कमी बनी रहती है। यही कारण है कि राष्ट्रीय स्तर पर वर्षा का औसत सामान्य से कम रहने के बावजूद कुछ राज्यों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। दूसरी ओर जिन क्षेत्रों में वर्षा सामान्य से कम रहेगी, वहां कृषि और जल संसाधनों पर दबाव बढ़ सकता है।

विशेषज्ञों के अनुसार जुलाई का महीना खरीफ कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। धान, मक्का, सोयाबीन, कपास, दालें और तिलहन जैसी प्रमुख फसलों की बुवाई इसी अवधि में बड़े पैमाने पर होती है। यदि पर्याप्त वर्षा नहीं होती तो किसानों को सिंचाई पर अतिरिक्त निर्भर रहना पड़ सकता है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं सीमित हैं, वहां फसल उत्पादन प्रभावित होने की आशंका भी बढ़ जाती है। यही कारण है कि मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान पर कृषि विशेषज्ञ विशेष नजर बनाए हुए हैं। कम वर्षा का प्रभाव केवल खेती तक सीमित नहीं रहता। जलाशयों, बांधों और नदियों में जल संचयन भी वर्षा पर निर्भर करता है। यदि जुलाई में अपेक्षित वर्षा नहीं होती तो पेयजल आपूर्ति, सिंचाई परियोजनाओं और जलविद्युत उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है। कई राज्यों में पहले से ही जल संरक्षण और जल प्रबंधन की योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि भविष्य में संभावित जल संकट से निपटा जा सके।

मौसम विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि जहां वर्षा सामान्य से कम रहेगी, वहां गर्मी और उमस का असर अधिक महसूस किया जा सकता है। बादलों की आवाजाही के बावजूद यदि पर्याप्त बारिश नहीं होती तो तापमान और आर्द्रता दोनों बढ़ सकते हैं। इससे लोगों को असहज मौसम का सामना करना पड़ सकता है, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में गर्मी और उमस का प्रभाव अधिक रहने की संभावना है। विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून के मासिक पूर्वानुमान का उद्देश्य सरकारों, किसानों, जल संसाधन विभागों और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को समय रहते तैयारी का अवसर देना होता है। इसी आधार पर फसल प्रबंधन, सिंचाई योजनाओं, जल संरक्षण कार्यक्रमों और अन्य आवश्यक रणनीतियों को तैयार किया जाता है। कृषि वैज्ञानिक किसानों को स्थानीय मौसम पूर्वानुमान के अनुसार फसल चयन, सिंचाई प्रबंधन और जल संरक्षण उपाय अपनाने की सलाह भी दे रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि मासिक पूर्वानुमान पूरे महीने की औसत स्थिति को दर्शाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि पूरे महीने सभी स्थानों पर लगातार कम वर्षा होगी। मानसून के दौरान अलग-अलग समय पर वर्षा की तीव्रता और वितरण में परिवर्तन संभव है। इसलिए स्थानीय स्तर पर जारी मौसम बुलेटिन और चेतावनियों पर भी लगातार ध्यान देना आवश्यक होगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जुलाई के दौरान कुछ समय के लिए मानसून सक्रिय होता है तो कई क्षेत्रों में वर्षा की कमी की भरपाई भी हो सकती है। वहीं जिन इलाकों में सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान है, वहां स्थानीय प्रशासन को जलभराव और बाढ़ जैसी संभावित परिस्थितियों के लिए भी सतर्क रहने की आवश्यकता होगी।

फिलहाल देश की निगाहें जुलाई के मानसून पर टिकी हैं। किसानों से लेकर जल प्रबंधन एजेंसियां, ऊर्जा क्षेत्र, खाद्य आपूर्ति तंत्र और आम नागरिक सभी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि मानसून की वास्तविक प्रगति पूर्वानुमानों के अनुरूप रहती है या परिस्थितियों में बदलाव आता है। आने वाले सप्ताह यह तय करेंगे कि इस वर्ष का मानसून कृषि, अर्थव्यवस्था और जनजीवन के लिए कितनी राहत लेकर आता है और किन क्षेत्रों में अतिरिक्त चुनौतियां खड़ी करता है।

## संपादकीय

# एआई विकास में मानवीय पहलू को मिले तरजीह

मानवता के लिए एआई के करिश्माई फायदे सामने आ रहे हैं। यह तकनीक स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास में क्रांतिकारी बदलाव लाने में सक्षम है लेकिन इससे प्राइवेसी, रोजगार, असमानता और मानवीय मूल्यों से जुड़े खतरे भी हैं। विशेषज्ञों व नीति नियंताओं का दायित्व है कि एआई के उपयोग में मानवीय गरिमा तथा प्रभावी वैश्विक नियमन को प्राथमिकता मिले। मानवता की सेवा में विज्ञान और नवाचार की असीम संभावनाओं का उपयोग करते हुए, मानव इतिहास के सबसे अहम दौर में, एआई क्रांति एक परिवर्तनकारी क्षण के रूप में दिखाई देती है। प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व चुनौतियों से निबटने में सशक्त बनाने वाली इसकी क्षमता उपलब्धियों पर गर्व करने को जायज ठहराती है, वह उपलब्धि जिससे देवता तक ईर्ष्या करें, जो मानवता की संयुक्त आविष्कारक क्षमता का सम्मान है। दोहराव वाले ऊबाऊ कार्यों का स्वचालन कर फुर्सत के लिए समय उपलब्ध कराना, जरूरी सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना, चिकित्सा में नई खोजें, दीर्घायु बनाना और बेहतर स्वास्थ्य सेवा यकीनी बनाना, जिसमें कैंसर जांच और घातक बीमारियों का पूर्वानुमान भी शामिल है, रोगियों की रोबोटिक देखभाल, वंचित वर्गों को मदद का अधिक प्रभावी और लक्षित वितरण, सभी के लिए शिक्षा और ज्ञान तथा आपदा प्रबंधन व मौसम पूर्वानुमान सहित अनेक तरीकों से पर्यावरण सततता बनाने में व्यापक योगदान, ये सभी अधिक समावेशी विकास उद्देश्य की दिशा में एआई के कुछ सबसे अहम योगदान हैं। फिर भी, मानव समाज के भविष्य और 'बुद्धिमत्ता की नियति' से जुड़े प्रश्नों पर दार्शनिकों, वैज्ञानिकों, नेताओं और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के बीच बहस जारी है। इनमें से कुछ उस एआई के भावी विकास व क्रियान्वयन पर विराम लगाने की अपील करते हैं, जो हमारी मानवता की अवधारणा को ही अपहृत कर सकती हो। वहीं एआई समर्थकों के दावे हैं कि इसकी मदद से वस्तुओं एवं सेवाओं की 'अद्भुत प्रचुरता' बनेगी और चेतावनी देते हैं कि नियमन से वैज्ञानिक प्रगति धीमा करने से उन अहम प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा जो मानवीय संवेदनाओं और सहस्राब्दियों तक चली सांस्कृतिक विकास-यात्रा के जरिये हमारे अस्तित्व की गहराइयों में समाहित भावनाओं के आधार पर नैतिक सुरक्षा-सीमाओं की आवश्यकता रेखांकित करते हैं। हम कौन हैं, और क्या हम मानवता के ऐसे नए नैरेटिव के लिए तैयार हैं जिसमें कार्यात्मक दक्षता और वादे मुताबिक भौतिक समृद्धि, मानवीय आकांक्षाओं व भावनाओं की गरिमा पर हावी हो जाए, यह एक अपरिहार्य प्रश्न है, जिसने तकनीकी चमत्कारों के आकर्षण में बहने को रोके रखा है। यह इसलिए अहम है कि एआई तकनीक मानवीय भावनाओं और अंतर्ज्ञान को समझने सहित संज्ञानात्मक कौशलों की नकल कर सकती है, व कई बार बेहतर प्रदर्शन भी कर सकती है। क्या हम अनंत तकनीकी उथल-पुथल और रोजगार बाज़ार में दीर्घकालिक अस्थिरता से पैदा 'तनाव की वैश्विक महामारी' के लिए तैयार हैं, साथ ही 'बेकार' हुए करोड़ों लोगों की अनुमानित भीड़ के लिए, जिसे तकनीकी परिवर्तन के प्रभावों से तालमेल बैठाने में असहनीय तनाव झेलना पड़ेगा? क्या हमारे पास ऐसे सामाजिक-आर्थिक मॉडल हैं जो व्यक्ति का आत्मसम्मान बचा पाएं और सबके लिए अपनत्व व भावनात्मक कल्याण से पूर्ण जीवन यकीनी बनाएं? ये दार्शनिक प्रश्न इंसानी नजरिये से पैदा होते हैं, जिसकी नींव मानवीय मूल्यों पर टिकी है। इस पर गंभीर चिंतन जरूरी है कि 'मन के उस गुप्त क्षेत्र को कैसे सुरक्षित रखा जाए, जहां से भावनाएं जन्मती हैं, प्रेरणा बहती है, व इच्छाएं स्पंदित होती हैं- मानवीय आत्मा का वह आत्मपरक पक्ष जो हम सब को अनिवार्यतः वह बनाता है, जो हम हैं'। डेटा गोपनीयता की कमजोरियां, दुष्प्रचार का प्रसार, चुनावी हेराफेरी, सुपर इंटेलिजेंट हथियार प्रणालियों के नियंत्रण से बाहर हो जाने की संभावना, एआई-सक्षम फ़िशिंग मुहिम तथा निगरानी एवं सेंसरशिप- ये कुछ भयावह संकेत हैं जो किसी प्रभावी वैश्विक नियामक के अभाव में सामाजिक उथल-पुथल की वजह बन सकते हैं। राष्ट्र और राज्यों की डिजिटल संप्रभुता बनाए रखना चुनौती है, क्योंकि डेटा पर नियंत्रण राष्ट्रीय सुरक्षा और देशों की रणनीतिक स्वायत्तता से जुड़ा है। इसलिए, एआई की वह दुनिया, जो मानवता का भविष्य बदलने में सक्षम है, उसे ऐसी नैतिक दृष्टि चाहिये जो तकनीकी प्रगति का तालमेल अच्छे और खुशहाल समाज की जरूरतों से बिठा सके। अति आत्मविश्वास बोध को टेरी ईगलटन ने ऐसे व्यक्त किया: 'अति आत्म-विश्वास अंततः विनाशकारी होता है, जिसने प्राचीन यूनानियों को भय के चलते आकाश की ओर देखने पर विवश कर दिया था'। स्पेनी दार्शनिक जोसे ओर्तेगा वाई गासेट याद दिलाते हैं 'हम ऐसे समय में जी रहे हैं, जब मनुष्य स्वयं को बेहद सक्षम मानता है, परंतु उसे नहीं पता कि क्या सृजित करे। वह सबका स्वामी है, किंतु खुद का नहीं।

# तुगलकी रास्ते से सत्ता की चाहत का हश्र शिवसेना जैसा होगा

> "शिवसेना यूबीटी की संख्या 9 से घटकर 3 रह गई है, जबकि शिंदे गुट की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, जिस महाराष्ट्र में एक दौर में एकीकृत शिवसेना की तूती बोलती थी, वहां उसकी बोलती भी लगभग बंद हो जाएगी। इस हालत के लिए शिवसेना खुद जिम्मेदार है।

डर और आतंक की राजनीति करने वाली शिवसेना घुटने पर आ चुकी है। नौबत यह आ गई है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार की मोदी सरकार को अपनी शर्तों पर नचाने का सपना देखने वाले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का ठिकाना छिन गया है। खुद सेना के सांसदों ने ही यह कारनामा कर दिखाया है। पार्टी के पूरी तरह से छिन्न भिन्न होने से लाचार उद्धव ने अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकस कर डाली। शिवसेना (यूबीटी) गुट के 6 सांसदों ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना का दामन थाम लिया। शिवसेना यूबीटी की संख्या 9 से घटकर 3 रह गई है, जबकि शिंदे गुट की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, जिस महाराष्ट्र में एक दौर में एकीकृत शिवसेना की तूती बोलती थी, वहां उसकी बोलती भी लगभग बंद हो जाएगी। इस हालत के लिए शिवसेना खुद जिम्मेदार है। कायदे—कानून भूल कर हर हालत में सिर्फ ताकत के बलबूते सत्ता पाने का ख्वाब देखने वाली शिवसेना यह भूल गई कि संविधान से इतर जाकर गैर लोकतांत्रिक तौर—तरीकों से सत्ता नहीं मिल सकती।

देश के अन्य क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की तरह सिकुडती शिवसेना का इतिहास कुछ ज्यादा ही काला रहा है। देश में यदि ममता बनर्जी के बाद किसी ने संविधान और कानून कायदों को ठेंगा दिया है तो वह है शिवसेना। शिवसेना ने भी ममता की तरह अपने ही कायदे कानून चलाने में कसर बाकी नहीं रखी। शिवसेना का ख्याल आते ही, देश के आम जनमानस में महाराष्ट्र में शिवसैनिकों की छवि उभरती थी, हाथों में डंडे या हथियार लिए शिवसैनिक और माथे पर शिवसेना का कपड़ा लपेटे हुए।

शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के दौरान बनी छवि से यह जाहिर होता था कि किसी को कानून की परवाह नहीं




है। कानून वही है जो शिवसेना बोल दे। किसी ने जरा भी विरोध करने का दुस्साहस किया तो उसकी खैर नहीं। महाराष्ट्र में चाहे सरकार किसी भी राजनीतिक दल की हो, शिवसेना का आतंक इतना जबरदस्त था कि किसी हिम्मत नहीं थी कि उनकी मनमानी के खिलाफ आवाज उठा सके। बाल ठाकरे ने बाहर से आकर मुंबई बसने वाले लोगों पर कटाक्ष करते हुए महाराष्ट्र को सिर्फ मराठियों का कहकर संबोधित किया।

खासतौर पर दक्षिण भारतीय लोगों के विरोध में उन्होंने कई भद्दे नारे भी दिए। शिवसेना का मुखपत्र माने जाने वाले 'सामना' समाचार पत्र में बिहार और उत्तर प्रदेश से मुंबई पलायन करने वाले लोगों को मराठियों के लिए खतरा बता, बाल ठाकरे ने महाराष्ट्र के लोगों को उनके साथ सहयोग ना करने की सलाह दी। साथ ही इन दो राज्यों से मुंबई बसने वाले नेताओं और अभिनेताओं की भी बाल ठाकरे द्वारा आलोचना की गई।

मोहम्मद अफजल की फांसी की सजा पर कोई फैसला ना सुनाने के लिए बाल ठाकरे ने तत्कालीन राष्ट्रपति ए.पी.जे. अबुल कलाम पर भी अभद्र टिप्पणियां की थी। वैलेंटाइन डे को हिंदू धर्म और संस्कृति के लिए खतरा बता, दुकानों और होटलों में तोड़-फोड करने के अलावा प्रेमी युगलों पर हमला, उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के लिए जनता में बाल ठाकरे के खिलाफ रोष उत्पन्न हो गया।

सचिन तेंदुलकर द्वारा भारत की तेजी से विकसित हो रही वाणिज्यिक राजधानी मुंबई को सभी भारतीयों का शहर बताने पर बाल ठाकरे भड़क उठे और उन्होंने सांप्रदायिक आधार पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तेंदुलकर "मराठी मानसिकता को ठेस पहुंचा रहे हैं। ठाकरे और तेंदुलकर, जो मूल रूप से मराठी थे, के बीच हुई इस तीखी बहस ने राष्ट्रीय स्तर पर काफी सुर्खियां बटोरीं। शिवसेना का ताज नहीं मिलने पर अलग हुए भतीजे राज ठाकरे ने भी बाल ठाकरे के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की, किन्तु दाल नहीं गली। संसद सदस्य जया बच्चन भी अपनी कथित "मराठी-विरोधी" टिप्पणियों के कारण राष्ट्रीय विवाद में फंस गईं। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र राज्य और वहां के लोगों का राष्ट्रीय भाषा की आड़ में अपमान करने के लिए जया बच्चन से सार्वजनिक माफी मांगने का आह्वान किया। डर के मारे बच्चन और उनके पति, अभिनेता अमिताभ बच्चन ने सार्वजनिक माफी जारी करते हुए कहा कि वे हिंदी में इसलिए बोले क्योंकि वे उत्तर प्रदेश (उत्तर भारत) से आए थे।

मुंबई या महाराष्ट्र में जिसे रहना है और कारोबार चलाना है, उसे शिवसेना की सारी शर्तों पूरी करनी होती थी। शिवसेना के आगे सिर झुकाने वालों, बॉलीवुड के फिल्मी सितारे, उद्योगपति, क्रिकेटर सहित तमाम दिग्गज हस्तियां शामिल थी। मीडिया भी शिवसेना के बारे में खबर छापने या टीवी पर दिखाने से पहले कई बार सोचता था। यह सब शिवसैनिकों का खौफ था। देश के दूसरे किसी राज्य में ऐसा तांडव किसी राजनीतिक दल का कभी देखने को नहीं मिला, जैसा शिवसेना ने महाराष्ट्र में दिखाया था।

कई दशकों तक शिवसेना की दहशत की यह छाप बनी रही। बाला साहेब के बाद उनके बेटे उद्धव ठाकरे और गद्दी नहीं मिलने के कारण शिवसेना छोड़ कर अलग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) बनाने वाले भतीजे राज ठाकरे ने भी इसी नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की। सत्ता नहीं मिलने पर राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने मवालियों वाला तरीका अपनाया और इसको नाम दिया मराठी मानुष और मराठी अस्मिता का।

राजनीति चमकाने के लिए मनसे भाषा और संस्कृति को मुद्दा बना कर गैरकूननी हरकते करने में कसर बाकी नहीं रखी। इसके बावजूद किसी भी तरह के चुनावों में सफलता हासिल नहीं हो सकी। देश के राजनीतिक दलों के लिए शिवसेना और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का हश्र सीखने लायक सबक है। राज्य के विकास के बजाए कानून हाथ में लेकर सत्ता कायम करने की चाहत अंततः क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के लिए घातक साबित होगी।

## प्रेरणा

# सादगी का सम्राट और सत्य का अमर प्रहरी : संत कबीर की चेतना से आलोकित मानवता का पथ

भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि जब-जब समाज अंधविश्वास, विभाजन, अन्याय और नैतिक पतन के दौर से गुजरा, तब-तब इस पावन भूमि ने ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया जिन्होंने अपने विचारों और जीवन से नई दिशा प्रदान की। संत कबीरदास ऐसे ही युगद्रष्टा संत थे, जिन्होंने न केवल भक्ति को नया आयाम दिया, बल्कि मनुष्य को स्वयं से परिचित कराने का भी अद्भुत प्रयास किया। वे किसी संप्रदाय, जाति, धर्म या वर्ग के संत नहीं थे, बल्कि संपूर्ण मानवता के संत थे। उनकी वाणी में सत्य का तेज, करुणा की मधुरता, तर्क की दृढ़ता और जीवन की सहजता का ऐसा अद्भुत संगम था जिसने उन्हें कालजयी बना दिया। कबीरदास का संपूर्ण जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्चा संत वही है जो समाज की विसंगतियों को पहचानकर उनके विरुद्ध निर्भीकता से खड़ा हो और साथ ही प्रेम, समानता तथा आत्मबोध का मार्ग भी दिखाए।

कबीर पंथ की मान्यता के अनुसार संत कबीरदास का जन्म संवत 1455 विक्रमी, अर्थात 1398 ईस्वी में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन काशी में हुआ था। उनके गुरु वैष्णव संत स्वामी रामानंद थे, जिनसे उन्हें आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त हुई। कबीर स्वयं कहते हैं—"काशी में परगट भये हैं, रामानंद चेताये।" यह पंक्ति केवल उनके गुरु का स्मरण नहीं, बल्कि भारतीय संत परंपरा में गुरु की सर्वोच्च भूमिका का भी परिचायक है। यद्यपि उनके जन्म को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित हैं, परंतु उनके जीवन का वास्तविक महत्व उनके कर्म, विचार और समाज पर पड़े प्रभाव में निहित है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि महानता किसी कुल, वंश या सामाजिक प्रतिष्ठा की मोहताज नहीं होती, बल्कि सत्य के प्रति अटूट निष्ठा और मानवता के प्रति समर्पण ही व्यक्ति को अमर बनाते हैं।

संत कबीर का जीवन अत्यंत साधारण था, किंतु उनके विचार असाधारण थे। वे बुनकर का कार्य करते थे और अपने श्रम से जीवनयापन करते थे। उन्होंने कभी संत होने का प्रदर्शन नहीं किया और न ही अपने चारों ओर चमत्कारों का वातावरण बनाया। उनके लिए श्रम ही साधना था और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धर्म। उन्होंने लोगों को यह संदेश दिया कि जो व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर की आराधना समझकर करता है, वही वास्तविक भक्त है। कबीर का यह दृष्टिकोण भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में कर्मयोग का अत्यंत व्यावहारिक रूप प्रस्तुत करता है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जीवन की पवित्रता बाहरी वस्त्रों, तिलक, माला या विशेष वेशभूषा से नहीं, बल्कि मन की निर्मलता और व्यवहार की सत्यनिष्ठा से निर्धारित होती है। कबीरदास की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे समाज की हर उस परंपरा का विरोध करते थे जो मनुष्य को मनुष्य से अलग करती थी। उस समय समाज जातिगत ऊंच-नीच, धार्मिक कट्टरता, रूढ़ियों और कर्मकांडों में बुरी तरह उलझा हुआ था। ब्राह्मण अपने जन्म का अभिमान करते थे, तो दूसरी ओर मुस्लिम समाज में भी बाहरी धार्मिक प्रदर्शन को ही आध्यात्मिकता का पर्याय मान लिया गया था। कबीर ने दोनों पक्षों की कमियों पर समान रूप से प्रहार किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ईश्वर मंदिर और मस्जिद की दीवारों में कैद नहीं है, बल्कि हर जीव के भीतर विद्यमान है। उन्होंने मनुष्य को बाहर नहीं, अपने भीतर ईश्वर की खोज करने की प्रेरणा दी। यही कारण है कि उनके विचार किसी एक धर्म तक सीमित नहीं रहे, बल्कि संपूर्ण मानव समाज की धरोहर बन गए।

कबीरदास का व्यक्तित्व इतना व्यापक था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय उन्हें अपना संत मानते थे। उनके जीवन का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग उनके देहावसान से जुड़ा है। जब उनके अंतिम संस्कार का समय आया तो हिंदू उन्हें अग्नि संस्कार देना चाहते थे, जबकि मुसलमान उन्हें दफनाना चाहते थे। किंवदंती है कि जब उनके शरीर से कफन हटाया गया तो वहां शरीर के स्थान पर केवल पुष्प मिले। दोनों समुदायों ने उन पुष्पों को समान रूप से बांट लिया और अपने-अपने रीति-रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार किया। यह घटना केवल एक चमत्कार की कथा नहीं, बल्कि उस महान संदेश का प्रतीक है जिसे कबीर ने जीवन भर प्रचारित किया—धर्म का वास्तविक स्वरूप प्रेम, करुणा और एकता है, न कि संघर्ष और विभाजन। कबीरदास की सादगी उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान थी। एक लोकप्रिय कथा के अनुसार संत तुलसीदास उनसे मिलने उस स्थान पर पहुंचे जहां उनकी छोटी-सी झोपड़ी थी। वहां तक पहुंचने के लिए कसाइयों की दुकानों के बीच से गुजरना पड़ता था। तुलसीदास ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा कि इतने महान संत होकर भी वे ऐसे स्थान पर क्यों रहते हैं। कबीर ने मुस्कुराकर समझाया कि मनुष्य का मूल्य उसके निवास स्थान से नहीं, बल्कि उसके विचारों और आचरण से होता है। यदि मन निर्मल है तो कोई भी स्थान साधना के योग्य बन सकता है। उनके जीवन का यह प्रसंग बताता है कि वे बाहरी परिस्थितियों से अधिक आंतरिक पवित्रता को महत्व देते थे। यही कारण है कि उनकी सादगी ही उनकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति बन गई।

कबीर स्वयं को कभी विद्वान नहीं कहते थे। वे बड़े विनम्र भाव से स्वीकार करते थे कि उन्होंने कागज-कलम का सहारा नहीं लिया। इसके बावजूद उनकी वाणी में ऐसा गहन दर्शन है जिसने शताब्दियों से विद्वानों, दार्शनिकों और साधकों को प्रेरित किया है। उन्होंने ज्ञान को पुस्तकीय जानकारी तक सीमित नहीं माना, बल्कि उसे जीवन के अनुभव, आत्मबोध और सत्य के अभ्यास से जोड़ा। उनके दोहे और साखियां अत्यंत सरल भाषा में जीवन के गहरे रहस्यों को उद्घाटित करती हैं। यही कारण है कि उनकी वाणी गांव की चौपाल से लेकर विश्वविद्यालयों तक समान रूप से आदर के साथ पढ़ी और समझी जाती है। संत कबीर केवल आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने जाति-पांति, छुआछूत, धार्मिक कट्टरता, पाखंड, अंधविश्वास और सामाजिक भेदभाव का आजीवन विरोध किया। उनके अनुसार मनुष्य की पहचान उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके चरित्र, कर्म और विचारों से होती है। उन्होंने ब्राह्मण और शूद्र के बीच किसी प्रकार का अंतर स्वीकार नहीं किया। वे मानते थे कि ईश्वर की भक्ति पर किसी जाति, वर्ग या समुदाय का अधिकार नहीं हो सकता। उनका यह विचार उस समय की सामाजिक व्यवस्था के लिए अत्यंत क्रांतिकारी था और आज भी सामाजिक समरसता की दिशा में प्रेरणास्रोत बना हुआ है। कबीरदास ने केवल समाज की बुराइयों का विरोध ही नहीं किया, बल्कि एक आदर्श जीवन की रूपरेखा भी प्रस्तुत की। उन्होंने सत्य, प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, परोपकार, संयम और सत्संग को जीवन का वास्तविक आभूषण बताया। दूसरी ओर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और लालच को मनुष्य की आत्मिक उन्नति का सबसे बड़ा बाधक माना।

# किडनैप कर किया गैंगरेप, सिगरेट से दागा और सड़क पर फेंक दी क्षत-विक्षत लाश, कश्मीरी पंडित सरला भट्ट की कहानी

14 अप्रैल 1990 श्रीनगर का शेर कश्मीर इंस्टट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस सरला भट्ट नाम की एक 25 साल की नर्स अपना काम खत्म करके हॉस्टल के कमरे में आराम कर रही होती है। तभी अचानक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के हथियारबंद आतंकी उनके कमरे में घुसते हैं। बंदूक की नोक पर सरला को अगवा करते हैं। लगातार चार दिनों तक इस कश्मीरी पंडित नर्स का सामूहिक बलात्कार किया जाता है। उसे तरह-तरह की यातनाएं दी जाती हैं। फिर पांचवें दिन 18 अप्रैल को उसकी लाश श्रीनगर के डाउनटाउन में फेंक दी जाती है। खून से रिसता हुआ शरीर और शरीर में गोलियों के निशान और कई अंग कटे हुए होते हैं जो उसके साथ हुई क्रूरता की गवाही दे रहे थे। लाश के साथ एक हाथ से लिखा हुआ नोट भी पड़ा हुआ था जिसमें जेकेएलएफ के दहशतगर्दों ने सरला भट्ट को पुलिस का मुखबिर बताया था। उसकी हत्या करने की बात कबूली थी। 36 साल तक सरला का परिवार न्यायिक इंतजार में था। 2017 और 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने दो बार घाटी में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार की दोबारा जांच की याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन 12 अगस्त 2025 को स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस केस को फिर से खोला और अब यह खबर आई है कि एजेंसी ने यह केस सुलझा लिया है। कट टू 29 जून 2026 यानी करीब 36 साल बाद जम्मू कश्मीर लिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 29 जून को एक संदेश के साथ प्रेस नोट जारी किया। ना कोई आतंकी अपराध भुलाया जाएगा ना कोई अपराधी कानून की पकड़ से बच पाएगा। जम्मू कश्मीर पु बताया कि एजेंसी ने करीब 36 साल पुराने सरला भट्ट अपहरण और हत्याकांड मामले में श्रीनगर की टाडा कोर्ट में 737 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इसमें अलगाववादी संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी जेकेएलएफ के लीडर यासीन मलिक समेत पांच लोगों के नाम है। यासीन मलिक फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है और उम्र कैद की सजा काट रहा है। चार्ज शीट के मुताबिक सरला भट्ट को अगवा किया गया, टॉर्चर किया गया था और फिर उनकी हत्या कर दी गई थी। केस के पांच आरोपियों में से तीन की मौत हो चुकी है। जबकि एक आरोपी अभी फरार है। पुलिस जांच ये कर रही है कि हत्या यासीन मलिक के कहने पर की गई थी या फिर नहीं। आज हम सरला भट्ट केस की कहानी जानेंगे। कौन थी सरला भट्ट? 36 साल पहले किस तरह जेकेएलएफ के आतंकियों ने उनका अपहरण कर उनकी हत्या कर दी थी और इस मामले में यासिन मलिक का नाम कैसे जुड़ा। साल 1990 का दौर घाटी में रहने वाले अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडितों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। इसी खौफनाक दौर की एक बेहद दर्दनाक और रूह कंपा देने वाली कहानी है सरला भट्ट की। अनंतनाग की रहने वाली 27 वर्षीय सरला भट्ट पेशे से एक नर्स थीं, जो श्रीनगर के सौरा स्थित 'शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज' (SKIMS) में अपनी सेवाएं दे रही थीं। लेकिन कश्मीरी पंडित होने के कारण वे उस दौर में पनपे चरमपंथ की क्रूर शिकार बनीं।

यह खौफनाक सिलसिला 14 अप्रैल 1990 को शुरू हुआ। सरला भट्ट SKIMS के 'हब्बा खातून हॉस्टल' में थीं, जब हथियारबंद आतंकी बंदूक की नोक पर उनका अपहरण कर ले गए। अगले पांच दिनों तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार, इन पांच दिनों के दौरान आतंकियों ने उन्हें बंधक बनाकर रखा, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया और उन्हें अमानवीय यातनाएं दीं।

अपहरण के पांच दिन बाद, 19 अप्रैल 1990 को सरला भट्ट का बेहद क्षत-विक्षत और क्षत-विक्षत शव सड़क पर फेंका हुआ मिला। दरिंदगी की हद यह थी कि उनके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए गए थे। उनके बेजान जिस्म के पास आतंकियों ने एक नोट भी छोड़ा था, जिसमें अपनी इस बर्बरता को सही ठहराने के लिए सरला को पुलिस का 'मुखबिर' बताया गया था।

इस जघन्य हत्याकांड को लेकर निगीन पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 56/1990 दर्ज की गई थी। हालांकि, राष्ट्रीय दैनिक 'द हिंदू' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस आधिकारिक दस्तावेज में उनके साथ हुई यौन हिंसा (रेप) का कोई उल्लेख नहीं किया गया था, जो उस दौर की प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्था की कमियों को उजागर करता है। इस पूरे मामले में प्रतिबंधित संगठन जेकेएलएफ (JKLF) के तत्कालीन नेता पीर नूरुल हक शाह उर्फ 'एयर मार्शल' का नाम मुख्य आरोपी के रूप में सामने आया था।

SKIMS श्रीनगर के सौरा इलाके में स्थित था, जिसे कश्मीरी में 'सोवुर' भी कहा जाता है। उस समय यह इलाका जेकेएलएफ और उसके समर्थकों का गढ़ माना जाता था। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में घायल हुए जेकेएलएफ के सदस्यों को इलाज के लिए अक्सर इसी अस्पताल में लाया जाता था। भट्ट का उनसे अक्सर सामना होता था। जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, इन सदस्यों को शक होने लगा था कि SKIMS में काम करने वाली एक कश्मीरी पंडित नर्स, घायलों के बारे में जानकारी पुलिस या खुफिया एजेंसियों तक पहुंचा सकती है। भट्ट को कई बार धमकियां भी दी गईं, लेकिन उन्होंने नौकरी नहीं छोड़ी। 8 अप्रैल 1990 को, खुफिया जानकारी के आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने नरवारा में छापेमारी की और जेकेएलएफ के बड़े सदस्यों को पकड़ने की कोशिश की। उस समय वहाँ मौजूद मलिक ने पुलिस को देख लिया, लेकिन वह घायल होने के बावजूद भागने में कामयाब रहा। जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, चार्जशीट में कहा गया है कि मलिक ने यह नतीजा निकाला था कि शायद किसी कश्मीरी पंडित नर्स ने पुलिस को खबर दी थी। हालांकि, इस नतीजे का कोई सबूत नहीं था। इसके बजाय, एसआईए की चार्जशीट में साफ़ तौर पर कहा गया है कि भट पर मुखबिर होने का आरोप पूरी तरह से झूठा था और इसे एक पहले से सोची-समझी हत्या को अंजाम देने का बहाना बनाने के लिए गढ़ा गया था।

## अभियान

# आस्था का अद्भुत रहस्य : जब भगवान जगन्नाथ स्वयं स्वीकार करते हैं रोग, विश्राम और पुनर्जागरण की दिव्य लीला

भारतीय सनातन संस्कृति में ईश्वर केवल आराधना का विषय नहीं हैं, बल्कि वे जीवन के हर भाव, हर अनुभूति और हर संबंध के सहभागी हैं। यही कारण है कि भारत के मंदिरों में भगवान को केवल पूजा नहीं जाता, बल्कि उन्हें परिवार के सदस्य की तरह प्रेम, स्नेह और सम्मान दिया जाता है। उन्हें जगाया जाता है, स्नान कराया जाता है, वस्त्र पहनाए जाते हैं, भोजन कराया जाता है, विश्राम कराया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर उनका उपचार भी किया जाता है। यह परंपरा संसार की किसी अन्य धार्मिक व्यवस्था में शायद ही इस रूप में दिखाई देती हो। ओडिशा के श्रीक्षेत्र पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली 'अनासर' परंपरा इस जीवंत आध्यात्मिक दर्शन का सबसे विलक्षण उदाहरण है। स्नान पूर्णिमा के अवसर पर भगवान जगन्नाथ, उनके अग्रज बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा का 108 पवित्र कलशों से महाभिषेक किया जाता है। इसके बाद यह मान्यता है कि भगवान को ज्वर हो जाता है और वे चौदह दिनों तक सार्वजनिक दर्शन से दूर रहकर विश्राम एवं उपचार ग्रहण करते हैं। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की उस गहन संवेदनशीलता का प्रतीक है जिसमें ईश्वर और भक्त के बीच का संबंध औपचारिक नहीं, बल्कि आत्मीय और पारिवारिक होता है।

स्नान पूर्णिमा को जगन्नाथ संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वर्ष भर की सेवाओं और उत्सवों के बीच यह एक ऐसा अवसर होता है जब भगवान पहली बार सार्वजनिक रूप से स्नान मंडप पर विराजमान होकर लाखों श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं। मंदिर की प्राचीन परंपरा के अनुसार भगवान के विग्रहों को गर्भगृह से विशेष शोभायात्रा के साथ स्नान वेदी तक लाया जाता है। वैदिक ऋचाओं, शंखध्वनि, मृदंग, झांझ और भक्तों के जयघोष के बीच उनका महाभिषेक आरंभ होता है। 108 कलशों में भरा गया पवित्र जल केवल सामान्य जल नहीं होता, बल्कि धार्मिक विधानों के अनुसार शुद्ध किए गए जल में चंदन, पुष्प, सुगंधित द्रव्य तथा औषधीय तत्व भी सम्मिलित किए जाते हैं। इस दिव्य स्नान का उद्देश्य भगवान के प्रति श्रद्धा प्रकट करना ही नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण की मंगलकामना करना भी माना जाता है।

महाभिषेक के उपरांत भगवान के अस्वस्थ होने की परंपरा भारतीय आध्यात्मिक दर्शन का अत्यंत मार्मिक पक्ष प्रस्तुत करती है। सनातन विचारधारा में ईश्वर सर्वशक्तिमान होने के बावजूद अपने भक्तों के अनुभवों से स्वयं को अलग नहीं रखते। वे जीवन के प्रत्येक भाव को अपनी लीला का अंग बनाते हैं। भगवान जगन्नाथ का ज्वर इसी सत्य का प्रतीक है कि ईश्वर केवल उपदेश देने वाले देव नहीं, बल्कि मानव जीवन के सुख-दुःख, श्रम, थकान, विश्राम और पुनर्निर्माण के भी सहभागी हैं। भगवान का बीमार होना भक्तों को यह अनुभूति कराता है कि जो ईश्वर समस्त ब्रह्मांड का पालन करता है, वही अपने भक्तों के जीवन की छोटी-से-छोटी अनुभूति को भी समझता है। यह भाव भारतीय भक्ति परंपरा को अत्यंत मानवीय और आत्मीय बना देता है।

स्नान पूर्णिमा के तुरंत बाद आरंभ होने वाली अनासर अवधि चौदह दिनों तक चलती है। इस दौरान भगवान के सार्वजनिक दर्शन पूरी तरह बंद रहते हैं। मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं और भगवान को विशेष कक्ष में विश्राम कराया जाता है। इस अवधि में केवल परंपरागत दैतापति सेवक, विशिष्ट सेवायत और राजवैद्य ही भगवान की सेवा कर सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया अत्यंत गोपनीय मानी जाती है और सदियों से निर्धारित नियमों के अनुसार संपन्न होती आ रही है। भक्तों के लिए यह विरह का समय होता है, किंतु इसी विरह में उनकी भक्ति और अधिक प्रगाढ़ होती है। यह संदेश भी निहित है कि सच्चा प्रेम केवल मिलन में नहीं, बल्कि प्रतीक्षा और धैर्य में भी व्यक्त होता है।

अनासर काल में भगवान के दैनिक भोग और पूजा-पद्धति में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाते हैं। सामान्य दिनों में भगवान को विविध प्रकार के व्यंजन, मिष्ठान्न और महाप्रसाद अर्पित किए जाते हैं, किंतु बीमारी की अवस्था में उन्हें अत्यंत हल्का, सुपाच्य और औषधीय गुणों से युक्त आहार दिया जाता है। फल, पनीर, औषधीय जड़ी-बूटियों से निर्मित विशेष लड्डू, काढ़े और पारंपरिक आयुर्वेदिक मिश्रण उनके भोग का भाग बनते हैं। यह व्यवस्था भारतीय आयुर्वेद की उस वैज्ञानिक समझ को भी अभिव्यक्त करती है जिसमें रोग की अवस्था के अनुसार भोजन और औषधि दोनों को समान महत्व दिया गया है। भगवान के उपचार की यह परंपरा मानव समाज को भी यह प्रेरणा देती है कि स्वास्थ्य की रक्षा केवल औषधियों से नहीं, बल्कि संतुलित आहार, पर्याप्त विश्राम और संयमित जीवनशैली से होती है। अनासर अवधि का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष भगवान के विग्रहों का पुनर्सौंदर्यीकरण है। स्नान पूर्णिमा के महाभिषेक के कारण भगवान के विग्रहों पर लगे प्राकृतिक रंगों में परिवर्तन आ जाता है। इसलिए पारंपरिक चित्रकार परिवार अत्यंत श्रद्धा और गोपनीयता के साथ भगवान के स्वरूप का पुनः रंग-रोगन करते हैं। यह केवल कलात्मक कार्य नहीं, बल्कि एक पवित्र धार्मिक सेवा मानी जाती है। वनस्पतियों से निर्मित प्राकृतिक रंगों और पारंपरिक तकनीकों के माध्यम से भगवान को पुनः नवीन आभा प्रदान की जाती है। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद भगवान पहले से अधिक तेजस्वी और आकर्षक स्वरूप में भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं। यही कारण है कि अनासर के पश्चात होने वाले नवयौवन दर्शन का महत्व अत्यंत विशेष माना जाता है। चौदह दिनों तक भगवान के दर्शन न होने से श्रद्धालुओं की आस्था कहीं कम नहीं होती, बल्कि वह और अधिक प्रबल हो जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस अवधि में भगवान अलारनाथ के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। इसलिए पुरी से लगभग पच्चीस किलोमीटर दूर स्थित ब्रह्मगिरि का अलारनाथ मंदिर श्रद्धालुओं का प्रमुख तीर्थ बन जाता है। हजारों श्रद्धालु वहां पहुंचकर भगवान के दर्शन करते हैं और उसी श्रद्धा से पूजा-अर्चना करते हैं जैसे वे श्रीमंदिर में करते हैं। यह परंपरा इस तथ्य को भी स्थापित करती है कि ईश्वर किसी एक स्थान, एक स्वरूप या एक मंदिर तक सीमित नहीं हैं। भक्त की निष्कपट श्रद्धा जहां होती है, वहीं भगवान का साक्षात् अनुभव संभव हो जाता है। अनासर काल केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और प्रशासनिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान अलारनाथ मंदिर और पुरी क्षेत्र में लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए व्यापक सुरक्षा और व्यवस्थाएं की जाती हैं। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, आधुनिक सीसीटीवी निगरानी, चिकित्सा शिविर, स्वच्छता अभियान, यातायात नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अस्थायी व्यवस्थाएं की जाती हैं। यह आयोजन ओडिशा की सांस्कृतिक पहचान के साथ-साथ धार्मिक पर्यटन का भी प्रमुख आधार बन चुका है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलती है और हजारों परिवारों की आजीविका भी जुड़ी रहती है। अनासर की परंपरा का दार्शनिक अर्थ अत्यंत गहरा है। यह हमें सिखाती है कि प्रकृति में कोई भी शक्ति निरंतर सक्रिय नहीं रहती। सूर्य भी अस्त होता है, चंद्रमा भी घटता-बढ़ता है, ऋतुएं भी बदलती हैं और वृक्ष भी पतझड़ के बाद नए पत्तों से भर जाते हैं। उसी प्रकार जीवन में विश्राम भी उतना ही आवश्यक है जितना कर्म। भगवान जगन्नाथ का चौदह दिनों का विश्राम इसी सार्वभौमिक सत्य का प्रतीक है। यह संदेश आधुनिक जीवन के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक है, जहां निरंतर कार्य, प्रतिस्पर्धा और मानसिक तनाव के कारण मनुष्य स्वयं को विश्राम देने की आवश्यकता भूलता जा रहा है। भगवान की यह लीला हमें बताती है कि विश्राम कमजोरी नहीं, बल्कि नई ऊर्जा और नवसृजन का आधार है। अनासर समाप्त होने के बाद भगवान का नवयौवन दर्शन होता है। यह केवल नए श्रृंगार का अवसर नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से पुनर्जन्म, नवीकरण और नई शुरुआत का प्रतीक है। भगवान नवीन तेज, नवीन रंग और नवीन ऊर्जा के साथ अपने भक्तों के सामने आते हैं। इसके तुरंत बाद विश्वविख्यात रथयात्रा का शुभारंभ होता है, जिसमें भगवान स्वयं मंदिर से बाहर निकलकर जनसामान्य के बीच आते हैं। यह भारतीय संस्कृति के लोकतांत्रिक और समरस भाव का अनुपम उदाहरण है। यहां राजा और सामान्य नागरिक दोनों समान श्रद्धा के साथ भगवान के रथ की रस्सी खींचते हैं।

PRGI NO. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmdabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

# प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का सर्वसमावेशी विकास का लक्ष्य वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस से चरितार्थ हुआ है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

**▸▸ वडोदरा में चौथी वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का शानदार समापन**

**▸▸ 3 लाख 34 हजार करोड़ रुपए से अधिक के पूंजी निवेश के साथ 3759 एमओयू पर हुए हस्ताक्षर**

**▸▸ 1 लाख 97 हजार से अधिक संभावित रोजगार के अवसर होंगे पैदा**

**▸▸ केंद्रीय रक्षा मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने में गुजरात की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया**

**केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह**

▸▸ भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.78 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा

▸▸ आज भारत आत्मनिर्भरता के रथ पर सवार होकर वैश्विक स्तर पर हुंकार भर रहा है

▸▸ आज भारत इंटरनेशनल फोरम में कुछ बोलता है, तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है, प्रधानमंत्री ने दुनिया में भारत का परचम लहराया है

▸▸ गुजरातियों के पास चुनौतियों को अवसर में बदलने का गजब का साहस और जज्बा है

**मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल**

▸▸ रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ प्रधानमंत्री ने इंडस्ट्री और इकोनॉमी के लिए अनुकूल नीतियां और वातावरण बनाया है

▸▸ वाइब्रेंट समिट और वीजीआरसी जैसे आयोजन राज्य में उद्योगों और उद्योगकारों के विकास के लिए एक टेक ऑफ प्लेटफॉर्म हैं

▸▸ मौजूदा जियो-पॉलिटिकल हालात में प्रधानमंत्री ने भारतीय उद्योगों की पूरी तरह से रक्षा की है

▸▸ अपना व्यवसाय-उद्योग शुरू करने की लगन रखने वाले कुशल युवाओं को इनोवेशन और स्टार्टअप के जरिए आगे बढ़ने का अवसर मिला है

वडोदरा : केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की प्रेरक उपस्थिति में मंगलवार को वडोदरा में आयोजित मध्य गुजरात क्षेत्र की वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) का शानदार समापन हुआ। 'क्षेत्रीय आकांक्षाएं, वैश्विक महत्वाकांक्षाएं' की थीम के साथ गुजरात की एक विशिष्ट पहल के रूप में वीजीआरसी के चार संस्करण गुजरात में सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने चौथी वीजीआरसी की सफलता की गर्व से घोषणा करते हुए कहा कि वडोदरा में मध्य गुजरात की इस वीजीआरसी में कुल मिलाकर 3 लाख 34 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ 3759 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके चलते आने वाले दिनों में राज्य में 1 लाख 97 हजार संभावित रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

**रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह**

कॉन्फ्रेंस के समापन समारोह में मुख्य भाषण देते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। 2014 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 46 हजार करोड़ रुपए था, जो पिछले दशक में बढ़कर 1 लाख 78 हजार करोड़ रुपए हो गया है। इसके अलावा, भारत ने 39 हजार करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट भी किया है।

उन्होंने कहा कि गुजरात ने हमेशा देश को दिशा दिखाई है। गुजरात की धरती ने देश को महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसी विभूतियां दी हैं। इसी धरती ने प्रधानमंत्री के रूप में इस देश को श्री नरेन्द्र मोदी जी को दिया है। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत का कद बढ़ा है। पहले भारत की बातों को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता था, लेकिन आज भारत इंटरनेशनल फोरम में कुछ बोलता है, तो सारी

दुनिया कान खोलकर सुनती है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने सारी दुनिया में भारत के परचम को लहराया है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि गुजरात की सबसे बड़ी ताकत यहां के लोगों की मानसिकता है। चुनौतियों को अवसर में बदलने का एक गजब का जज्बा और साहस है। 2003 में शुरू हुई वाइब्रेंट गुजरात समिट की नींव तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रखी थी, जो अब दो दशकों बाद विकसित भारत 2047 के संकल्प से जुड़कर एक व्यापक आंदोलन बन गई है।

श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र की सुरक्षा और आर्थिक विकास को एक-दूसरे का पूरक बताते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था और सुरक्षा गहराई से जुड़ी होती हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी महान राष्ट्र आर्थिक ताकत, तकनीकी शक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा की तीन मजबूत नींवों पर खड़ा होता है। जो इन क्षेत्रों में आगे होगा, वही लीड लेगा और वहीं इनोवेशन होगा।

श्री राजनाथ सिंह ने वर्तमान जियो पॉलिटिकल हालात में भारत की आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में डिफेंस सेक्टर में अभूतपूर्व बदलाव हुए हैं। पहले हम अपनी रक्षा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर थे, लेकिन आज भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ रहा है। हम इस क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए लाइसेंस, पॉलिसी और पारदर्शिता लाकर उनमें विश्वास पैदा किया है।

डिफेंस सेक्टर में गुजरात की महत्वपूर्ण भूमिका का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि गुजरात की रोबस्ट इंडस्ट्री, स्पिरिट और कौशल देश की आत्मनिर्भरता की यात्रा में बड़ा योगदान दे सकती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि गुजरात डिफेंस क्षेत्र में हब बन सकता है।

वडोदरा का उल्लेख करते हुए उन्होंने गर्व से कहा कि आज वडोदरा भारत की पहली प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट फैसिलिटी का केंद्र बन गया है। टाटा-एयरबस सी-295 प्रोजेक्ट एक अभूतपूर्व मील का पत्थर है और हम सभी के लिए गर्व की बात है।

उन्होंने साणंद और धोलेरा के सेमीकंडक्टर हब को टेक्नोलॉजी का आधारस्तंभ बताया। रक्षा मंत्री के अनुसार गुजरात का केमिकल और पेट्रोकेमिकल का मजबूत आधार भी डिफेंस सेक्टर के उत्पादन में योगदान दे सकता है। इसके अलावा, गुजरात के इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, पोर्ट, मैरीटाइम और शिप बिल्डिंग जैसे क्षेत्र भी डिफेंस प्रोडक्शन में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।

रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में गुजरात को देश का लीडर बताते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ग्रीन एनर्जी भी डिफेंस सेक्टर के लिए नया रास्ता खोल सकती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हमारी पॉलिसी हमेशा पारदर्शी रही है और हर क्षेत्र की इंडस्ट्री को पर्याप्त सहयोग दिया जाता है।

श्री राजनाथ सिंह ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि आज भारत आत्मनिर्भरता के रथ पर सवार होकर वैश्विक स्तर पर हुंकार भर रहा है। भारत की यह विकास यात्रा असाधारण है। उन्होंने कहा कि हमें भविष्य की कल्पना नहीं, बल्कि उसका निर्माण करना है, जिसमें भारत के अलग-अलग उत्पाद ग्लोबल मार्केट में हों। भारत की आत्मनिर्भरता का अर्थ दुनिया से अलगाव नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर सभी के साथ भागीदारी है।

**मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल**

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सर्वसमावेशी विकास का जो लक्ष्य रखा है, उसे गुजरात ने इस वीजीआरसी के माध्यम से साकार किया है।

इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल का विजन, क्षेत्रीय ताकत, परंपरा और प्रतिभा को वैश्विक स्तर पर ले जाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता इस वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस की सफलता के मूल में है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ इंडस्ट्री और इकोनॉमी के लिए अनुकूल नीतियां और वातावरण तैयार किया है। एक समय 'फ्रेजाइल फाइव' यानी पांच नाजुक में से एक मानी जाने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।

मुख्यमंत्री ने इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया कि मौजूदा जियो-पॉलिटिकल हालात में भी प्रधानमंत्री ने उद्योगों के हितों की पूरी रक्षा की है।

उन्होंने कहा कि आज दुनिया को श्री मोदी साहब के नेतृत्व पर भरोसा है। इतना ही नहीं, विदेशों में रहने वाले भारतीयों का भी देश के नेतृत्व पर विश्वास बढ़ने से फॉरेन रेमिटेंस (विदेश से अपने परिवार या प्रियजन को पैसा भेजना) में भी बड़ी वृद्धि देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि 2025 के एक ही वर्ष में 13 लाख करोड़ रुपए के रेमिटेंस देश में आया है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने अपना व्यवसाय शुरू करने की लगन वाले कुशल युवाओं और छोटे-बड़े उद्योगकारों को इनोवेशन और स्टार्टअप के जरिए आगे बढ़ने का अवसर दिया है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि वाइब्रेंट समिट और वीजीआरसी जैसे आयोजन उद्योगों और उद्योगकारों के विकास के लिए एक टेक ऑफ प्लेटफॉर्म बन गए हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा बतौर मुख्यमंत्री 2003 में शुरू की गई वाइब्रेंट समिट की अपार सफलता के चलते गुजरात ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट बन गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा राज्य के क्षेत्रीय विकास के जरिए संतुलित विकास का एक नया अध्याय रचकर विकसित भारत 2047 के लिए सभी के सहयोग से विकसित गुजरात को आगे रखना है।

**केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह**

समापन समारोह में केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने गुजरात को अंतर्देशीय मत्स्यपालन के क्षेत्र में देश का 'पावरहाउस' बनाने के लिए एक सटीक रोडमैप पेश किया।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गुजरात के पास न केवल लंबी तटरेखा है, बल्कि अंतर्देशीय मत्स्यपालन की अपार क्षमता भी है। राज्य के अनेक जिलों के गांवों में मौजूद तालाबों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इन संसाधनों का बेहतर उपयोग करके ब्लू इकोनॉमी को गति दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में उपलब्ध कुल खारे पानी का एक तिहाई हिस्सा अकेले गुजरात में है, जो झींगा के उत्पादन के लिए अत्यंत मजबूत आधार प्रदान करता है।

मछली निर्यात क्षेत्र में मौजूद संभावनाओं का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्तमान में कुल मत्स्य निर्यात में गुजरात के अंतर्देशीय मत्स्य उद्योग का हिस्सा केवल 2 फीसदी है, जिसे बढ़ाने का बड़ा अवसर गुजरात के पास है। इसके लिए उन्होंने मत्स्यपालन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग, हैचरी सिस्टम को मजबूत बनाने और कोल्ड चेन इन्वेस्टमेंट में वृद्धि करने तथा श्रेष्ठ परिवहन सुविधा जैसे प्रेरक सुझाव दिए।

उन्होंने राज्य सरकार, हितधारकों, वैज्ञानिकों और उद्यमियों से एक साथ मिलकर गुजरात को अंतर्देशीय मत्स्यउद्योग का ग्लोबल हब बनाने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाने का आह्वान किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह कॉन्फ्रेंस 'विकसित गुजरात से विकसित भारत' के सपने को साकार करने में एक सार्थक मंच साबित होगी।

समापन समारोह में जाइडेक्स समूह के चेयरमैन श्री अजय रांका और रूबामिन के चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक श्री अतुल डालमिया ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

कार्यक्रम की शुरुआत में उद्योग विभाग की अपर मुख्य सचिव सुश्री ममता वर्मा ने वीजीआरसी के आयोजन से लेकर सफलता तक के सारे पहलुओं का विस्तार से वर्णन किया।

समापन समारोह में विभिन्न क्षेत्रों के हस्तकला कारीगरों और उद्यमियों को सम्मानित भी किया गया।

समापन समारोह में राज्य मंत्री डॉ. मनीषा वकील, उद्योग जगत के अग्रणी, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्य सहित प्रतिनिधिगण और कई वरिष्ठ सचिव मौजूद रहे।

जीएसएफसीयू के अध्यक्ष श्री पी.के. तनेजा ने आभार व्यक्त किया।

# गांधीनगर में 127 करोड़ रुपए की लागत से होगा भारतीय शिक्षक शिक्षा संस्थान (आईआईटीई) के नूतन भवन तथा छात्रावास का निर्माण

**▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा राज्य मंत्री की उपस्थिति में शिलान्यास किया**

**▸▸ आईआईटीई जैसे संस्थानों के माध्यम से भारत राष्ट्र निर्माता शिक्षक देकर वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा : शिक्षा मंत्री डॉ. प्रद्युमन वाजा**

गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना से स्थापित हुए राज्य विश्वविद्यालय भारतीय शिक्षक शिक्षा संस्थान (आईआईटीई) के नए एवं अत्याधुनिक भवन का गांधीनगर में निर्माण होगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने 127 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले इस नूतन भवन का मंगलवार को शिक्षा मंत्री डॉ. प्रद्युमन वाजा तथा राज्य मंत्रियों सर्वश्री त्रिकमभाई छांगा और रिवाबा जाडेजा की उपस्थिति में शिलान्यास किया।

इस प्रस्तावित नए भवन में अकादमीय भवन, आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला तथा परिसंवाद सभागार और राज्य पुस्तकालय व संग्रहालय जैसी सुविधाओं के अतिरिक्त; खेलों के लिए खेल मैदान, आधुनिक सुविधाओं से युक्त 600 से अधिक छात्र-छात्राओं की क्षमता वाले छात्रावास का निर्माण किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि इस आईआईटीई की स्थापना समाज को उत्तम शिक्षक उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विशिष्ट विजन से की गई है।

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री डॉ. प्रद्युमन वाजा ने कहा कि आज केवल भवन के निर्माण का प्रारंभ नहीं हुआ है, अपितु भारत के भविष्य के निर्माण में अमूल्य योगदान देने वाले उत्तम शिक्षकों के निर्माण के एक नए युग का शुभारंभ हुआ है। भारत केवल साधारण शिक्षक ही नहीं, वरन् 'राष्ट्र निर्माता' शिक्षक तैयार कर वैश्विक स्तर पर अग्रणी भूमिका निभाए और विदेशों में भी श्रेष्ठ शिक्षक प्रदान करे; ऐसे भगीरथ दृष्टिकोण को यह संस्थान आज नई ऊँचाई पर ले जा रहा है।

श्री वाजा ने कहा कि विश्व स्तरीय शिक्षक तैयार करने के लिए विश्व स्तरीय संस्थान स्थापित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी विचार से वर्ष 2010 में इस विशिष्ट विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। संस्थान के सर्वांगीण

विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 127 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया गया है। इस अनुदान अंतर्गत परिसर में नए अकादमीय तथा संकाय भवनों, अत्याधुनिक वर्ग खंडों, आधुनिक विज्ञान प्रयोगशालाओं, परिसंवाद सभागार, स्टेट-ऑफ-द आर्ट लाइब्रेरी, संग्रहालय और खेल-कूद की उत्कृष्ट सुविधाएँ की जाएंगी। इसके अलावा; लगभग 600 से अधिक छात्र-छात्राओं के लिए सभी आधुनिक सुविधाओं से सज्ज छात्रावास का भी निर्माण किया जाएगा।

शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन में गुजरात देशभर में अग्रसर रहा है। यह नई शिक्षा नीति बहुविषयी शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार तथा कौशल आधारित पाठ्यक्रमों पर विशेष बल देती है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आईआईटीई को अब एक 'मल्टीडिसिप्लीनरी यूनिवर्सिटी' के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न ज्ञान शाखाओं के समन्वय के साथ सर्वग्राही शिक्षा एवं अनुसंधान को प्रोत्साहन देने वाले सात नए 'यूनिवर्सिटी स्कूल्स' का गठन किया गया है।

उन्होंने जोड़ा कि शिक्षा समाज एवं राष्ट्र के विकास का सबसे शक्तिशाली माध्यम है और शिक्षक क्लासरूम से ही राष्ट्र का निर्माण करता है। आज जिस भवन का शिलान्यास किया गया है, वह केवल सिमेंट-कंक्रीट का ढाँचा नहीं, अपितु विकसित गुजरात से विकसित भारत के उज्ज्वल भविष्य की एक सुदृढ़ आधारशिला है।

इस अवसर पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री श्री त्रिकमभाई छांगा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दार्शनिक विचार के साथ स्थापित यह विश्वविद्यालय केवल अक्षर ज्ञान देने तक सीमित नहीं है, अपितु शिक्षा क्षेत्र में नया चिंतन व अनुसंधान लाकर आधुनिक गुजरात और आधुनिक भारत के निर्माण में आधारभूत भूमिका भी निभाता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नई शिक्षा नीति के व्यापक क्रियान्वयन के बीच यह विश्वविद्यालय आगामी समय में देशभर में शिक्षा के आचार, विचार एवं व्यवहार में आमूल परिवर्तन लाकर एक विशिष्ट स्थान प्राप्त करेगा।

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वडनगर के बी. एन. हाईस्कूल में जिन आदरणीय शिक्षकों एवं गुरुजनों से शिक्षा प्राप्त की थी, उनका मुख्यमंत्री द्वारा भावपूर्वक अभिवादन-सम्मान किया गया।

इस अवसर पर सभी उपस्थित महानुभावों के करकमलों से एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) पाठ्यक्रम का डिजिटल अनावरण किया गया।

इस समारोह में गांधीनगर की महापौर श्री मीराबेन पटेल, राज्यसभा सदस्य श्री राजेश शुक्ल, आईआईटीई के प्राध्यापक, अकादमीय प्रमुख, निदेशक, प्राचार्य तथा विद्यार्थी उपस्थित रहे।

# एसआईआर के चलते मतदाता सूची से 6 करोड़ नाम हटाए गए, नागरिकों के मतदान अधिकारों और भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं

**(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।**

विशेष गहन मतदाता सूची संशोधन (एसआईआर) प्रक्रिया शुरू हुए एक साल से अधिक समय बीत चुका है और यह वर्तमान में 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी है। रिपोर्टों के अनुसार, एसआईआर प्रक्रिया के कारण अब तक मतदाता सूची से लगभग 6 करोड़ नाम हटाए जा चुके हैं।

और यह एक गंभीर मामला है जो यह सवाल खड़ा करता है कि क्या वाकई इतने सारे लोग वोट देने के अयोग्य हैं? सबसे बड़ी चिंता यह है कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, उनका भविष्य क्या होगा? इसके अलावा, अगर उन्हें वोट देने के अयोग्य माना जाता है, तो इससे उनके अन्य अधिकारों पर क्या असर पड़ेगा? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिम बंगाल और बिहार में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के बाद ऐसी खबरें सामने आई हैं कि दोनों राज्यों की संशोधित मतदाता सूची के आंकड़ों को अब सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल किया जाएगा। यानी, यह आशंका है कि जिन लोगों के नाम इस नई मतदाता सूची में हैं, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा और जिन्हें सूची से बाहर कर दिया गया है, उन्हें इन योजनाओं के लाभ से वंचित रखा

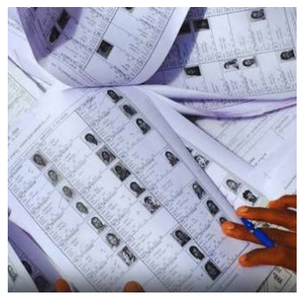

जाएगा।

इसलिए, सूची से बाहर किए गए लोग अब अपनी नागरिकता की स्थिति को लेकर चिंतित हैं। उन्हें सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की सूची से भी बाहर किए जाने का खतरा है। परिणामस्वरूप, उनका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी है कि तकनीकी कारणों या समय पर दस्तावेज प्राप्त करने में असमर्थता के कारण किसी भी पात्र व्यक्ति को मतदान के अधिकार से वंचित न किया जाए। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र तभी सही मायने में फलता-फूलता है जब योग्य नागरिकों के मतदान अधिकारों की रक्षा की जाती है और चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित किए जाते हैं। तभी सच्चा लोकतंत्र देखने को मिलेगा।

# आगरा में भाजपा पार्षद ने सीवर में खड़े होकर अपना जन्मदिन मनाया और स्वच्छता व्यवस्था की उपेक्षा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया

**(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।**

आगरा में भाजपा नगर निगम कर्मचारी किशन नायक ने प्रशासन द्वारा स्वच्छता संबंधी शिकायतों की अनदेखी के विरोध में अपना जन्मदिन उफनते नाले में खड़े होकर मनाया। इस प्रतीकात्मक विरोध का उद्देश्य निवासियों द्वारा सामना की जा रही लगातार सीवेज समस्याओं को उजागर करना था। किशन नायक ने आरोप लगाया कि खुले नालों और अस्वच्छ परिस्थितियों के बारे में बार-बार शिकायत करने के बावजूद, स्वच्छता विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है।

अधिकारियों की निष्क्रियता ने उन्हें विरोध के अपरंपरागत तरीके अपनाने के लिए मजबूर कर दिया। इस घटना ने नागरिक बुनियादी ढांचे की स्थिति और लंबे समय से चली आ रही जन शिकायतों के प्रति स्थानीय अधिकारियों की उदासीनता पर एक बहस छेड़ दी है।

# पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल ने पल्स पोलियो अभियान में रचा कीर्तिमान,पहले ही दिन 3,569 बच्चों का टीकाकरण कर पश्चिम रेलवे में रहा अव्वल

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल के चिकित्सा विभाग ने राष्ट्रव्यापी पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अभियान के प्रथम दिन ही मंडल ने 3,569 बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन (OPV) की खुराक पिलाकर पश्चिम रेलवे के सभी मंडलों में सर्वाधिक टीकाकरण का गौरव प्राप्त किया।

28 जून, 2026 से प्रारंभ हुए इस राष्ट्रव्यापी अभियान का संचालन मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के मार्गदर्शन एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मनोज कुमार की देखरेख में किया गया। अभियान को प्रभावी एवं व्यापक बनाने के लिए मंडलीय रेलवे अस्पताल, 10 स्वास्थ्य इकाइयों तथा रेलवे स्टेशनों एवं ट्रेनों सहित मंडल भर में 52 पल्स पोलियो टीकाकरण बूथ स्थापित किए गए, जिससे अधिकतम बच्चों तक सहज एवं त्वरित पहुंच सुनिश्चित की जा सकी।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सुव्यवस्थित योजना, समर्पित कार्यप्रणाली एवं चिकित्सा विभाग की सक्रिय भागीदारी के परिणामस्वरूप अभियान के पहले ही दिन 3,569 बच्चों को पोलियो रोधी दवा की खुराक पिलाई गई। इस उपलब्धि ने भावनगर मंडल को पश्चिम रेलवे के सभी मंडलों में प्रथम स्थान दिलाया।

बूथ आधारित टीकाकरण के उपरांत 29 एवं 30 जून को विशेष अनुवर्ती अभियान चलाकर चिकित्सा टीमों ने मंडल की सभी रेलवे कॉलोनियों में घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया। इस दौरान ऐसे बच्चों की पहचान कर उन्हें पोलियो की खुराक पिलाई गई, जो किसी कारणवश पहले दिन टीकाकरण से वंचित रह गए थे। इस अभियान का उद्देश्य पांच वर्ष से कम आयु के प्रत्येक पात्र बच्चे तक पोलियो रोधी दवा पहुंचाना था।

यह उल्लेखनीय उपलब्धि चिकित्सा विभाग की प्रभावी योजना, चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल कर्मियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं स्वयंसेवकों की अथक मेहनत तथा रेलवे कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के सक्रिय सहयोग का परिणाम है।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने कहा कि भावनगर मंडल का चिकित्सा विभाग प्रत्येक बच्चे को पोलियो जैसी गंभीर एवं स्थायी विकलांगता उत्पन्न करने वाली बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। यह उपलब्धि भारत सरकार के 'पोलियो मुक्त भारत' के संकल्प को साकार करने की दिशा में पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल के महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान को भी रेखांकित करती है।

# पश्चिम रेलवे द्वारा अहमदाबाद–दरभंगा एवं गांधीधाम–भागलपुर स्पेशल ट्रेनों के फेरों का विस्तार,मार्ग परिवर्तन के साथ विशेष ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा

यात्रियों की सुविधा तथा ग्रीष्मकालीन एवं आगामी त्योहारों के दौरान बढ़ती हुई यात्रा मांग को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे ने अहमदाबाद–दरभंगा तथा गांधीधाम–भागलपुर विशेष किराया स्पेशल ट्रेनों के फेरों का विस्तार करने का निर्णय लिया है। साथ ही, उत्तर रेलवे के लखनऊ स्टेशन पर आरएलडीए (RLDA) कार्य के कारण इन ट्रेनों का संचालन परिवर्तित मार्ग से किया जाएगा।

ट्रेन संख्या 09465/09466 अहमदाबाद–दरभंगा–अहमदाबाद साप्ताहिक स्पेशल

ट्रेन संख्या 09465 अहमदाबाद–दरभंगा साप्ताहिक स्पेशल (प्रत्येक शुक्रवार) के फेरे 03 जुलाई, 2026 से 31 जुलाई, 2026 तक तथा ट्रेन संख्या 09466 दरभंगा–अहमदाबाद साप्ताहिक स्पेशल (प्रत्येक सोमवार) के फेरे 06 जुलाई, 2026 से 03 अगस्त, 2026 तक विस्तारित किए गए हैं।

यह ट्रेन परिवर्तित मार्ग वाया छायापुरी, रतलाम, उज्जैन, गुना, बिना, वीरांगना

लक्ष्मीबाई झांसी, गोविंदपुरी, फतेहपुर, प्रयागराज, ज्ञानपुर रोड, वाराणसी, औड़िहार, गाजीपुर सिटी, छपरा, मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर होकर चलेगी।

ट्रेन संख्या 09451/09452 गांधीधाम–भागलपुर–गांधीधाम साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन संख्या 09451 गांधीधाम–भागलपुर साप्ताहिक स्पेशल (प्रत्येक शुक्रवार) के फेरे 03 जुलाई, 2026 से 31 जुलाई, 2026 तक तथा ट्रेन संख्या 09452 भागलपुर–गांधीधाम साप्ताहिक स्पेशल (प्रत्येक सोमवार) के फेरे 06 जुलाई, 2026 से 03 अगस्त, 2026 तक विस्तारित किए गए हैं।

यह ट्रेन परिवर्तित मार्ग वाया भचाऊ, सामाखियाली, ध्रांगध्रा, अहमदाबाद, नडियाद, दाहोद, रतलाम, भवानी मंडी, कोटा जंक्शन, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, हिण्डौन सिटी, बयाना जंक्शन, भरतपुर, मथुरा, हाथरस सिटी, कासगंज, फर्रुखाबाद, कानपुर सेंट्रल, फतेहपुर, प्रयागराज, ज्ञानपुर रोड, वाराणसी, औड़िहार, गाजीपुर सिटी, छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बरौनी जंक्शन, बेगूसराय, मुंगेर, सुल्तानगंज एवं भागलपुर होकर चलेगी।

ट्रेन संख्या 09465 एवं 09451 की बुकिंग 01 जुलाई, 2026 से सभी पीआरएस काउंटरों एवं आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा से पूर्व ट्रेन के समय, ठहराव एवं अन्य विवरण की जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें।

# वडोदरा में वीजीआरसी-मध्य गुजरात के दूसरे दिन आयोजित हुआ ‘आत्मनिर्भर भारत इन एयरोस्पेस एंड डिफेंस’ विषय पर सेमिनार

**▸▸ एयरोस्पेस और डिफेंस संबंधी सेमिनार में केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की विशेष उपस्थिति**

**▸▸ ‘एक स्टार्टअप के रूप में आप सीधे रक्षा मंत्री की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं :’ केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह**

**▸▸ रक्षा क्षेत्र में चार कंपनियों द्वारा 2550 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एमओयू, 4 हजार से अधिक रोजगार का सृजन होगा**




गांधीनगर, 30 जून : मध्य गुजरात क्षेत्र के लिए वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) के चौथे संस्करण का आयोजन 29 व 30 जून, 2026 के दौरान वडोदरा स्थित गुजरात राज्य फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स (जीएसएफसी) यूनिवर्सिटी में किया गया है। इस दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन मंगलवार को ‘आत्मनिर्भर भारत इन एयरोस्पेस एंड डिफेंस’ विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की विशेष उपस्थिति में गुजरात में रक्षा क्षेत्र में 2550 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एमओयू किए गए। रक्षा मंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित सहभागियों से भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने तथा उसे आगे ले जाने के लिए विभिन्न सुझाव सुने और उनके साथ संवाद किया।

रक्षा मंत्री ने सहभागियों के साथ संवाद करते हुए कहा, “औद्योगिक क्षेत्र तथा रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहाँ उपस्थित स्टार्टअप्स या उद्योगों को कोई समस्या हो, सवाल हो अथवा आपके कोई सुझाव हो, तो हमें बताएँ। आप बताएँ कि सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है ? हम यह जानना चाहते हैं।”

इस अवसर पर उपस्थित सहभागियों ने टेस्टिंग सुविधाओं को ग्लोबल स्तरीय कैसे बनाया जा सके, टेस्टिंग सुविधाओं का निर्माण, रक्षा क्षेत्र में गुजरात की भूमिका, देश में बेसिक मटेरियल्स की उपलब्धता तथा गुजरात में डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण और अन्य सम्बद्ध सुझाव प्रस्तुत किए।

**एक स्टार्टअप के रूप में आप सीधे रक्षा मंत्री की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं : रक्षा मंत्री**

रक्षा क्षेत्र में कार्यरत तथा ड्रोन निर्माण करने वाले अमृत डिफेंस के फाउंडर नील वैद्य ने रक्षा मंत्री के समक्ष विनम्रतापूर्वक एक सुझाव प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कई बार उन्हें उनके उत्पादों व सेवाओं के लिए योग्य ‘एंड यूजर’ की पहचान करने में कठिनाई आती है। इसके बारे में उन्होंने रक्षा मंत्री से मार्गदर्शन मांगा।

प्रत्युत्तर में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा, “मैं लगातार डिफेंस क्षेत्र में कार्य करने वाले स्टार्टअप्स के साथ मुलाकात करता रहता हूँ। उनकी समस्याओं, उन्हें जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उसकी जानकारी मुझे मिलती रहती है। हमारे साथ अधिकारी भी मौजूद रहते हैं। आवश्यक निर्देश मौके पर ही दे दिए जाते हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न कॉन्फ्रेंसें और कार्यरत लगातार होते रहते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि कोई कॉन्फ्रेंस हो या न हो, मीटिंग भी भले ही नहीं हो, एक स्टार्टअप के रूप में आप सीधे रक्षा मंत्री की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।”

**रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण एमएसएमईस के बिना अधूरा है : अपर उद्योग आयुक्त**

सेमिनार की शुरुआत गुजरात के अपर उद्योग आयुक्त तथा इंडेक्स्ट-बी के प्रबंध निदेशक (एमडी) श्री के. सी. संपत (आईएएस) द्वारा की गई। उन्होंने सेमिनार में होने वाली चर्चाओं का संदर्भ दिया और गुजरात के डिफेंस इकोसिस्टम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विदेशों से आयात किए जाने वाले रक्षा संसाधन हमारे देश में बनाए जाएँ और इसके लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमईस) किस तरह सहायक हो सकते हैं; इस बारे में सेमिनार में चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि लघु उद्योग रक्षा क्षेत्र में बहुत सहयोग कर रहे हैं। एमएसएमईस रक्षा क्षेत्र के लिए आवश्यक पार्ट्स बना सकेंगे और उन्हें तेजी से डिलीवर कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि डिफेंस क्षेत्र का स्वदेशीकरण एमएसएमईस के बिना अधूरा है।

इस सेमिनार में लघु उद्योग भारती के महासचिव श्री हंसराज गजेरा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)-गांधीनगर के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर (सिस्टम्स) कमोडोर श्री मनीष त्रिपाठी (सेवानिवृत्त), भारतीय वायुसेना के एयर हेडक्वार्टर में एयरोस्पेस डिजाइन निदेशालय के एयर कमोडोर श्री ज्ञानदीप सिंह, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की महानिदेशक (पीसी एंड एसआई) डॉ. चंद्रिका कौशिक ने विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखे और प्रेजेंटेशन दिए।

लघु उद्योग भारती के महासचिव श्री हंसराज गजेरा ने ‘रोल ऑफ एमएसएमईस इन डिफेंस इंडिजिनाइजेशन’ (रक्षा स्वदेशीकरण में एमएसएमईस की भूमिका) विषय पर प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में भारत सरकार की ‘आत्मनिर्भर भारत’ की पहल का स्वागत किया और कहा कि देश के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाने एवं आत्मनिर्भरता हासिल करने में एमएसएमईस की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में एमएसएमईस अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, कारण कि उनके पास इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटक (स्पेयरपार्ट्स) सप्लाई करने की क्षमता है। गुजरात के पास इस सेगमेंट के लिए एक सुदृढ़ आधार और उसमें अपार संभावनाएँ रही हुई हैं। आईआईटी-गांधीनगर के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर (सिस्टम्स) कमोडोर मनीष त्रिपाठी (सेवानिवृत्त) ने ‘द इवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ वॉरफेयर’ (युद्ध के बदलते परिदृश्य) विषय पर प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने कहा, “आज के समय में युद्ध की परंपरागत व्याख्या बदल रही है। डिजिटल युग में सूचना का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में रक्षा क्षेत्र में साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनोमस सिस्टम्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी और सुरक्षित संचार व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।”

उन्होंने जोड़ा, “भविष्य की रक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखकर हमें ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करनी होगी, जो केवल आज की आवश्यकताएँ ही पूरी न करे, बल्कि आने वाले वर्षों की सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए भी सक्षम बने। आईआईटी-गांधीनगर जैसे संस्थानों, सरकार और सशस्त्र बलों के बीच सहयोग आत्मनिर्भर भारत के रक्षा क्षेत्र को नई दिशा दे सकता है। आज युद्ध केवल मैदान तक सीमित नहीं रहा; सूचना, साइबर क्षेत्र तथा नई टेक्नोलॉजी भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी रक्षा टेक्नोलॉजी का विकास समय की जरूरत है।” भारतीय वायुसेना के एयर हेडक्वार्टर में एयरोस्पेस डिजाइन महानिदेशालय के एयर कमोडोर ज्ञानदीप सिंह ने एयरोस्पेस तथा डिफेंस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर विशेष वक्तव्य देते हुए कहा, “आज के समय में सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ भौतिक सीमाओं से आगे बढ़ रही हैं। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए देश को पूरी तरह तैयार रहने की जरूरत है और रक्षा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की विदेशी निर्भरता को कम करना जरूरी है।” उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लिए आर्थिक विकास, सुदृढ़ नीति ढाँचा और कुशल मानल संसाधन में निवेश पर बल देते हुए कहा, “एयरोस्पेस तथा डिफेंस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सहयोग, नवाचार एवं त्वरित प्रक्रियाओं पर ध्यान देना होगा। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए उद्योगों, अनुसंधान संस्थानों तथा सशस्त्र बलों के बीच सहयोग बहुत ही आवश्यक है।”

डीआरडीओ की महानिदेशक (पीसी एंड एसआई) डॉ. चंद्रिका कौशिक ने एयरोस्पेस तथा डिफेंस क्षेत्र में स्वदेशी टेक्नोलॉजी के विकास पर बल देते हुए कहा, “डीआरडीओ द्वारा ब्रह्मोस, आकाश जैसी विभिन्न स्वदेशी रक्षा प्रणालियाँ विकसित की जा रही हैं। भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रककर हाइपरसोनिक सिस्टम्स, स्पेस तथा साइबर क्षमताएँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेसर आधारित सिस्टम्स और सुरक्षित संचार जैसी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है।”

उन्होंने जोड़ा, “रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए अनुसंधान, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी का विकास जरूरी है। सैनिकों की सुविधाएँ एवं क्षमताएँ बढ़ाने के लिए नई टेक्नोलॉजी विकसित करने और प्रोटोटाइप विकास के लिए एमएसएमई क्षेत्र का सहयोग बढ़ाने की भी आवश्यकता है। एकेडेमिया, उद्योग एवं सरकार के बीच मजबूत सहयोग रक्षा क्षेत्र में भारत को अधिक आत्मनिर्भर बना सकता है।”

**‘आयात निर्भरता से स्वदेशी क्षमता तक : आत्मनिर्भर एयरोस्पेस और रक्षा इकोसिस्टम का निर्माण’ विषय पर पैनल चर्चा**

रक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों के प्रेजेंटेशन तथा संबोधन के बाद ‘आयात निर्भरता से स्वदेशी क्षमता तक : आत्मनिर्भर एयरोस्पेस तथा रक्षा इकोसिस्टम का निर्माण’ विषय पर आयोजित एक पैनल चर्चा में राष्ट्रीय रक्षाशक्ति यूनिवर्सिटी के प्रो-वाइस प्रेसीडेंट श्री कल्पेश एच. वंड्रा ने मॉडरेटर की भूमिका निभाई। पैनल चर्चा में यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज के निदेशक (प्रोजेक्ट्स) एयर कमोडोर डॉ. जयंता कुमार साहू (सेवानिवृत्त), श्री राम एयरोस्पेस के संस्थापक एवं सीईओ श्री संदीप सतानी, फोर्ब्स 30 यू 30 एशिया 2024 में इनसाइड एफपीवी ड्रोन्स के सीईओ श्री अर्थ चौधरी, जैवल एयरोस्पेस के संस्थापक एवं सीईओ श्री विपुल वाछाणी, हजीरा स्थित एल एंड टी प्रिसीजन इंजीनियरिंग एंड सिस्टम्स के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक, परियोजना प्रबंधक श्री आनंद मिस्त्री, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड के सहायक महाप्रबंधक श्री आशुतोष सिंह बघेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के महाप्रबंधक श्री श्रीनिवास के., इन-स्पेसई के स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग के निदेशक एयर वाइस मार्शल श्री धनंजय खोट (सेवानिवृत्त), गुजरात उद्योग एवं वाणिज्य मंडल (जीसीसीआई) की डिफेंस टास्क फोर्स के चेयरमैन श्री अंशुल नाणावटी और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के चेयरमैन श्री पीयूष तंबोली सहभागी हुए।

**गुजरात में रक्षा क्षेत्र में 2550 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एमओयू**

केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में चार कंपनियों ने गुजरात में रक्षा क्षेत्र में निवेश के लिए एमओयू किए। इनमें दिनेश चंद्र डिफेंस सिस्टम्स प्रा. लि. द्वारा 800 करोड़ रुपए, श्री राम एयरोस्पेस एंड डिफेंस एलएलपी द्वारा 150 करोड़ रुपए, श्री खोडियार हेवी इंजीनियरिंग प्रा. लि. द्वारा 100 करोड़ रुपए और एसआरके इलेक्ट्रॉनिक्स एलएलपी द्वारा 1500 करोड़ रुपए के एमओयू किए गए। यह कुल निवेश 2550 करोड़ रुपए का है; जो गुजरात में खेडा, राजकोट, वडोदरा तथा अहमदाबाद में किया जाएगा। रक्षा क्षेत्र में होने वाले इस निवेश द्वारा 4 हजार से अधिक रोजगार का सृजन होगा। ये कंपनियाँ डिफेंस सिस्टम्स, डिफेंस संसाधन, एयरोस्पेस टूलिंग व इंजन तथा यूएवी सिस्टम्स और ऐप्लिकेशन हार्डवेयर के निर्माण क्षेत्र में कार्यरत हैं।

इस कार्यक्रम में रक्षा क्षेत्र के विभिन्न स्टार्टअप्स को सम्मानित किया गया। राज्य के उद्योग एवं खान विभाग की अपर मुख्य सचिव श्री ममता वर्मा ने आभार व्यक्त करते हुए सेमिनार का समापन किया।

## यात्रियों की सुविधा हेतु अहमदाबाद मण्डल की 03 जोड़ी ट्रेनों में अस्थायी रूप से अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे

यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ तथा यात्रा मांग को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे ने निम्नलिखित ट्रेनों में अस्थायी रूप से अतिरिक्त कोच जोड़ने का निर्णय लिया है। इसका विवरण निम्नानुसार हैः

ट्रेन संख्या 20485/20486 साबरमती–जैसलमर–साबरमती इंटरसिटी एक्सप्रेस में 02 एसी 3-टियर एवं 01 स्लीपर कोच साबरमती से 03 जुलाई, 2026 से 02 अगस्त, 2026 तक तथा जैसलमर से 01 जुलाई, 2026 से 31 जुलाई, 2026 तक अस्थायी रूप से जोड़े जाएंगे।

ट्रेन संख्या 20492/20491 साबरमती–जैसलमेर–साबरमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस में 02 एसी 3-टियर एवं 01 स्लीपर कोच साबरमती से 01 जुलाई, 2026 से 31 जुलाई, 2026 तक तथा जैसलमेर से 02 जुलाई, 2026 से 01 अगस्त, 2026 तक अस्थायी रूप से जोड़े जाएंगे।

ट्रेन संख्या 20987/20988 उदयपुर सिटी–असारवा–उदयपुर सिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में 01 सेकेंड सीटिंग कोच असारवा से 02 जुलाई, 2026 से 01 अगस्त, 2026 तक तथा उदयपुर सिटी से 01 जुलाई, 2026 से 31 जुलाई, 2026 तक अस्थायी रूप से जोड़ा जाएगा।

यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा से पूर्व ट्रेन के समय, ठहराव एवं अन्य विवरण की जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें।

## सुस्त मानसून से खेती पर संकट के बादल, खरीफ बुवाई में 23 फीसदी गिरावट; धान, दाल और तिलहन की कम बोआई से बढ़ी महंगाई की आशंका

नई दिल्ली। दक्षिण-पश्चिम मानसून की धीमी प्रगति ने देश की कृषि व्यवस्था के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। समय पर पर्याप्त वर्षा नहीं होने का सीधा असर खरीफ फसलों की बुवाई पर दिखाई देने लगा है। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष 25 जून तक खरीफ फसलों की कुल बुवाई पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में लगभग 23 प्रतिशत कम दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आने वाले दिनों में मानसून सामान्य गति नहीं पकड़ता, तो इसका प्रभाव केवल कृषि उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खाद्य आपूर्ति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महंगाई पर भी व्यापक असर पड़ सकता है। विशेष रूप से धान, दालों और तिलहन जैसी प्रमुख फसलों के रकबे में आई उल्लेखनीय कमी ने सरकार, कृषि वैज्ञानिकों और बाजार विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है।

कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 25 जून तक देश में खरीफ फसलों की बुवाई केवल 182.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हो सकी, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि तक यह आंकड़ा 236.46 लाख हेक्टेयर था। यानी एक वर्ष में लगभग 53 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बुवाई नहीं हो सकी। यह गिरावट केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संकेत देती है कि देश के अनेक हिस्सों में किसान अभी भी पर्याप्त वर्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं और खेतों में बुवाई शुरू नहीं कर पाए हैं।

सबसे अधिक चिंता धान की खेती को लेकर जताई जा रही है, क्योंकि यह देश की खाद्य सुरक्षा का आधार माना जाता है। इस वर्ष धान की बुवाई में लगभग 25.17 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। 25 जून तक धान का रकबा घटकर केवल 25.75 लाख हेक्टेयर रह गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में कहीं अधिक क्षेत्र में रोपाई हो चुकी थी। धान की खेती मुख्य रूप से समय पर मानसून पर निर्भर करती है और वर्षा में देरी का सीधा प्रभाव इसकी रोपाई पर पड़ता है। यदि आने वाले दिनों में भी पर्याप्त बारिश नहीं होती, तो उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तिलहन फसलों की स्थिति और भी अधिक चिंताजनक दिखाई दे रही है। आंकड़ों के अनुसार, तिलहन की बुवाई में 53.33 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई है। यह कमी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश पहले से ही खाद्य तेलों की घरेलू मांग पूरी करने के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। यदि घरेलू उत्पादन प्रभावित होता है, तो आयात पर निर्भरता और बढ़ सकती है, जिसका असर खाद्य तेलों की कीमतों पर भी दिखाई दे सकता है।

दालों की खेती भी इस बार मानसून की सुस्ती से अछूती नहीं रही है। कृषि मंत्रालय के अनुसार, दालों का रकबा भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत कम हो गया है। दालें भारतीय भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इनके उत्पादन में कमी आने पर बाजार में कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका बनी रहती है। पिछले वर्षों का अनुभव बताता है कि दालों की उपलब्धता में कमी होने पर सरकार को आयात बढ़ाने और बाजार हस्तक्षेप जैसे कदम उठाने पड़ते हैं।

मौसम विभाग के आंकड़े भी कृषि क्षेत्र की चिंताओं को और गहरा कर रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, 24 जून तक देश में सामान्य से 42 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई है। मानसून की यह कमी केवल किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अनेक हिस्सों में इसका प्रभाव महसूस किया जा रहा है। सबसे अधिक प्रभावित मध्य भारत रहा है, जहां सामान्य से लगभग 59 प्रतिशत कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। यह क्षेत्र सोयाबीन, कपास, दालों और अन्य खरीफ फसलों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहां बारिश की कमी का सीधा असर बुवाई और आगे चलकर उत्पादन पर पड़ सकता है।

मौसम वैज्ञानिकों ने इस वर्ष अल-नीनो की स्थिति को लेकर भी चिंता व्यक्त की है। प्रशांत महासागर में विकसित हो रही अल-नीनो परिस्थितियां दक्षिण-पश्चिम मानसून की तीव्रता और वितरण को प्रभावित कर सकती हैं। यदि आने वाले महीनों में अल-नीनो और मजबूत होता है, तो देश के विभिन्न हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना बढ़ सकती है। हालांकि मानसून अभी अपने प्रारंभिक चरण में है, फिर भी विशेषज्ञ लगातार इसकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं।

## कक्षा में शिक्षक का थप्पड़ बना जिंदगी भर का दर्द, 10वीं के छात्र का फटा कान का पर्दा; अहमदाबाद की घटना ने खड़े किए स्कूलों में सुरक्षा और अनुशासन पर गंभीर सवाल

अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद से शिक्षक और विद्यार्थी के रिश्ते को झकझोर देने वाली एक गंभीर घटना सामने आई है। निकोल क्षेत्र स्थित एक विद्यालय में कथित तौर पर एक शिक्षक ने बिना किसी स्पष्ट कारण के 10वीं कक्षा के छात्र को इतना जोरदार थप्पड़ मार दिया कि उसके कान का पर्दा फट गया। चोट इतनी गंभीर थी कि छात्र के कान से खून निकलने लगा और उसे सुनने में दिक्कत होने लगी। चिकित्सकीय जांच में कान के पर्दे के क्षतिग्रस्त होने की पुष्टि होने के बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया। पीड़ित छात्र के पिता की शिकायत पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।



प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना विद्यालय में शारीरिक शिक्षा (पीटी) की कक्षा के दौरान हुई। गुजराती माध्यम में पढ़ने वाला 10वीं कक्षा का छात्र अपने कुछ साथियों के साथ मैदान में बैठा हुआ था। उसी समय आसपास 10वीं और 12वीं कक्षा के कुछ अन्य विद्यार्थी आपस में बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान अंग्रेजी विषय के शिक्षक लक्ष्मण वहां पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने बिना किसी स्पष्ट कारण के छात्र को खड़ा किया और उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। बताया जा रहा है कि छात्र का उस शिक्षक के साथ पहले किसी प्रकार का विवाद या अनुशासनहीनता का कोई मामला भी नहीं था।

थप्पड़ लगते ही छात्र को तेज दर्द महसूस हुआ और उसके बाएं कान से खून बहने लगा। घटना के बाद विद्यालय परिसर में मौजूद लोगों में भी हड़कंप मच गया। परिजनों को सूचना मिलने पर छात्र को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे कान, नाक और गला (ईएनटी) विशेषज्ञ को दिखाया गया। चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान डॉक्टरों ने पाया कि थप्पड़ का प्रभाव इतना गंभीर था कि छात्र के बाएं कान का पर्दा फट गया है। चिकित्सकों के अनुसार इस प्रकार की चोट सुनने की क्षमता पर भी असर डाल सकती है और समय पर उचित उपचार नहीं मिलने पर स्थिति और गंभीर हो सकती है।

चिकित्सकीय रिपोर्ट मिलने के बाद छात्र के परिजनों ने इस घटना पर कड़ा विरोध जताया। छात्र के पिता ने अहमदाबाद के कृष्णनगर पुलिस थाने में आरोपी शिक्षक लक्ष्मण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि बिना किसी गलती के उनके बेटे के साथ शारीरिक हिंसा की गई, जिसके कारण उसे गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और घटना से जुड़े सभी तथ्यों को एकत्र किया जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार घटना के बाद विद्यालय प्रशासन ने भी मामले को गंभीरता से लिया। सोमवार सुबह विद्यालय के ट्रस्टी, आरोपी शिक्षक और छात्र के अभिभावकों के बीच बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शिक्षक ने कथित रूप से अपनी गलती स्वीकार की। हालांकि छात्र के पिता ने केवल मौखिक स्वीकारोक्ति को पर्याप्त नहीं माना। उन्होंने विद्यालय प्रशासन से लिखित आश्वासन की मांग की कि यदि भविष्य में उनके बेटे को इस चोट के कारण सुनने में स्थायी समस्या, कान से जुड़ी अन्य चिकित्सकीय जटिलता या बहरापन जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसके इलाज का पूरा चिकित्सकीय और आर्थिक दायित्व विद्यालय और संबंधित शिक्षक उठाएंगे।

परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों ने छात्र की स्थिति को गंभीर बताया है और आवश्यकता पड़ने पर उसके कान का ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। इस कारण परिवार मानसिक तनाव से गुजर रहा है। उनका कहना है कि विद्यालय बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा का स्थान होता है, जहां विद्यार्थियों को भयमुक्त वातावरण मिलना चाहिए। यदि शिक्षक ही हिंसक व्यवहार करेंगे तो इससे बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

यह घटना एक बार फिर विद्यालयों में अनुशासन के नाम पर शारीरिक दंड के मुद्दे को चर्चा के केंद्र में ले आई है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की शारीरिक हिंसा न केवल उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि यह उनके आत्मविश्वास, मानसिक संतुलन और सीखने की प्रक्रिया पर भी नकारात्मक असर डाल सकती है। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में संवाद, परामर्श और सकारात्मक अनुशासन पर जोर दिया जाता है, जबकि शारीरिक दंड को पूरी तरह अस्वीकार्य माना गया है।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यदि जांच में यह साबित होता है कि छात्र को शिक्षक के थप्पड़ से गंभीर शारीरिक चोट पहुंची है, तो संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस अब चिकित्सकीय रिपोर्ट, विद्यालय प्रशासन के बयान, प्रत्यक्षदर्शियों की जानकारी और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ा रही है।

इस घटना ने अभिभावकों के बीच भी चिंता बढ़ा दी है। उनका कहना है कि विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि नैतिक दायित्व भी है। वे चाहते हैं कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

फिलहाल छात्र चिकित्सकीय निगरानी में है और उसके उपचार की प्रक्रिया जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि विद्यालय प्रशासन भी आंतरिक स्तर पर पूरे घटनाक्रम की समीक्षा कर रहा है। अब सभी की नजर जांच के निष्कर्ष और आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई पर टिकी है।

## सूरत नगर निगम की 12 समितियों को मिला नया नेतृत्व, विकास कार्यों में तेजी लाने की तैयारी; महिलाओं और युवाओं को भी मिली अहम जिम्मेदारियां

सूरत। सूरत नगर निगम (एसएमसी) के प्रशासनिक ढांचे को नई गति देने और विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम की 12 वैधानिक एवं विशेष समितियों के नए चेयरमैन और उपाध्यक्षों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। लंबे समय से इन नियुक्तियों को लेकर चल रही चर्चाओं और राजनीतिक अटकलों पर विराम लगाते हुए पार्टी नेतृत्व ने अनुभव, संगठनात्मक सक्रियता, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, सामाजिक संतुलन और प्रशासनिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए नई टीम का गठन किया है। अब इन समितियों के माध्यम से शहर की आधारभूत सुविधाओं, स्वास्थ्य, जल प्रबंधन, परिवहन, आवास, कानून, सार्वजनिक निर्माण और सामाजिक कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

पार्टी नेतृत्व की सहमति से घोषित नई सूची के अनुसार स्वास्थ्य समिति की जिम्मेदारी अशोक रांदेरिया को सौंपी गई है, जबकि विक्रम देसाई को उपाध्यक्ष बनाया गया है। यह समिति नगर निगम के अस्पतालों, शहरी स्वास्थ्य केंद्रों, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं, रोग नियंत्रण कार्यक्रमों और नागरिक स्वास्थ्य सुविधाओं की निगरानी एवं सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। शहर की बढ़ती आबादी और स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए इस समिति की जिम्मेदारी काफी अहम मानी जा रही है।

सार्वजनिक निर्माण समिति की कमान राजेंद्र पटेल को सौंपी गई है तथा शीतल प्रतीक पटेल को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह समिति शहर की सड़कें, पुल, सार्वजनिक भवन, आधारभूत ढांचा परियोजनाएं तथा अन्य निर्माण कार्यों की योजना, स्वीकृति और निगरानी का दायित्व संभालेगी। नगर निगम की विकास परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन में इस समिति की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। जल समिति के चेयरमैन के रूप में रश्मिबेन साबू की नियुक्ति की गई है, जबकि महेश कुमार मकवाना उपाध्यक्ष होंगे। यह समिति शहर में पेयजल आपूर्ति, जल वितरण प्रणाली, नई पाइपलाइन परियोजनाओं, जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन से जुड़े सभी विषयों की जिम्मेदारी संभालेगी। तेजी से विस्तार कर रहे सूरत में निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना इस समिति की प्रमुख प्राथमिकताओं में रहेगा।

सीवरेज व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से गटर (सीवरेज) समिति की कमान रवींद्र विट्ठलभाई खेरनार को सौंपी गई है तथा रजनीत देसाई को उपाध्यक्ष बनाया गया है। मानसून के दौरान जलभराव, सीवरेज लाइन की क्षमता बढ़ाने, जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ करने और स्वच्छता संबंधी परियोजनाओं पर यह समिति विशेष ध्यान देगी। शहरी विकास के साथ मजबूत सीवरेज व्यवस्था को अत्यंत आवश्यक माना जाता है।

टाउन प्लानिंग समिति की अध्यक्षता महेंद्र देसाई करेंगे, जबकि अशोक मांगीलाल शाह उपाध्यक्ष होंगे। शहर के विस्तार, नई टाउन प्लानिंग योजनाओं, भूमि विकास, सड़क नेटवर्क और भविष्य की शहरी विकास योजनाओं को अंतिम रूप देने में इस समिति की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सूरत के तेजी से बढ़ते शहरी विस्तार को व्यवस्थित दिशा देने के लिए इस समिति के निर्णय विशेष महत्व रखते हैं।

नगर निगम के कानूनी मामलों की जिम्मेदारी कानून समिति को सौंपी गई है, जिसकी चेयरमैन मोहिनीबेन राठौड़ होंगी तथा काव्याबेन पटेल उपाध्यक्ष का दायित्व निभाएंगी। यह समिति न्यायालयों में लंबित मामलों, कानूनी सलाह, अनुबंधों और विभिन्न प्रशासनिक निर्णयों के विधिक परीक्षण की निगरानी करेगी।

सोशल वेलफेयर एवं आनंद-प्रमोद सांस्कृतिक समिति का नेतृत्व राजेश राणा करेंगे, जबकि ईश्वरभाई नरोला उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। यह समिति सामाजिक कल्याण योजनाओं, सांस्कृतिक गतिविधियों, मनोरंजन सुविधाओं तथा नागरिक सहभागिता से जुड़े कार्यक्रमों को बढ़ावा देने का कार्य करेगी।

हॉस्पिटल रिलीफ एवं हेल्थ प्रमोशन समिति की कमान अलकाबेन पाटिल को दी गई है और हेमाक्षीबेन चौहान को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह समिति अस्पतालों में रोगी सुविधाओं के विस्तार, स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों और जनस्वास्थ्य कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देगी।

हाउसिंग एवं पार्क्स समिति के चेयरमैन सुरेशभाई धमेलिया होंगे, जबकि विधिबेन चानाभाई राठौड़ उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगी। यह समिति आवास योजनाओं, सार्वजनिक उद्यानों, हरित क्षेत्र के विकास और नागरिकों के लिए मनोरंजन सुविधाओं के विस्तार का कार्य करेगी।

स्लम इम्प्रूवमेंट समिति की जिम्मेदारी दिग्विजयसिंह बराड़ को सौंपी गई है तथा वंदनाबेन घोघरी उपाध्यक्ष होंगी। झुग्गी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास, स्वच्छता, आवास सुधार और जीवन स्तर बेहतर बनाने की योजनाओं के क्रियान्वयन में यह समिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

लाइट एवं फायर समिति की चेयरमैन सोनूबेन आंबलिया बनाई गई हैं, जबकि सुधाबेन राजेश पांडे उपाध्यक्ष होंगी। यह समिति शहर की स्ट्रीट लाइट व्यवस्था, अग्निशमन सेवाओं, आपदा प्रबंधन और अग्नि सुरक्षा से जुड़े विषयों की निगरानी करेगी।

सार्वजनिक परिवहन समिति की कमान मनीषभाई चिमनभाई पटेल को सौंपी गई है तथा रीनासिंह अजीतसिंह राजपूत उपाध्यक्ष होंगी। यह समिति नगर परिवहन सेवाओं, बस संचालन, यातायात सुविधाओं तथा सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य करेगी।

घोषित सूची की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह रही कि पार्टी ने अनुभवी नेताओं के साथ-साथ युवा चेहरों और महिला प्रतिनिधियों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं। 12 समितियों में कई प्रमुख पद महिलाओं को दिए गए हैं, जिसे संगठन महिला नेतृत्व को प्रोत्साहन देने और प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रहा है। साथ ही नए और अनुभवी नेतृत्व के संतुलन के माध्यम से प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने का प्रयास भी किया गया है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नगर निगम की समितियां शहर के दैनिक प्रशासन और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की रीढ़ होती हैं। इन्हीं समितियों के माध्यम से सड़क, पानी, स्वच्छता, स्वास्थ्य, आवास, परिवहन, शहरी नियोजन और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। ऐसे में नई नियुक्तियों से विकास कार्यों में नई गति आने की उम्मीद की जा रही है।

नगर निगम के अनुसार, 7 जुलाई को संबंधित समितियों की पहली बैठक आयोजित की जाएगी। इसी बैठक में नव-नियुक्त चेयरमैन और उपाध्यक्षों की औपचारिक नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होगी। इसके बाद सभी पदाधिकारी अपना कार्यभार संभालेंगे और अपनी-अपनी समितियों के माध्यम से शहर के विकास एवं जनहित से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। नगर निगम प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व दोनों को उम्मीद है कि नई टीम के गठन से सूरत में विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और नागरिक सुविधाओं के संचालन को अधिक प्रभावी एवं उत्तरदायी बनाया जा सकेगा।